नौकरी या काम में मिलने वाली खुशी हमारे कार्य में पूर्णता लाती है। -अरस्तु

शीर्ष अदालत ने अपने ही फैसले को पलटते हुए कोटे में कोटा की व्यवस्था को मंजूरी देने का महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। लेकिन इसके क्रियान्वयन के लिए जरूरी आंकड़ों को जमा करना जटिल काम है। देखने वाली बात यह भी होगी कि राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं के मद्देनजर इसका कैसे उपयोग करते हैं।

कोटे में कोटा

सर्वोच्च न्यायालय की सात न्यायमूर्तियों की पीठ ने छह बनाम एक के बहुमत वाले अपने एक ऐतिहासिक निर्णय में 2004 के ईवी चिन्नैया मामले में दिए गए निर्णय को पलटते हुए आरक्षण के भीतर आरक्षण को मंजूरी दे दी है, जो सामाजिक न्याय व समानता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जाहिर है कि अब राज्य सरकारें नौकरियों व शिक्षा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति वर्ग में ज्यादा पिछड़ी जातियों को आरक्षण का लाभ दे सकेंगी। लेकिन यह उनकी इच्छा पर नहीं, बल्कि अपर्याप्त प्रतिनिधित्व वाले वर्गों के बारे में उनके स्पष्टीकरण पर आधारित होगा। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 341 और 342 में क्रमशः अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को अधिसूचित करने के विषय में संसद और राष्ट्रपति को अधिकार दिए गए हैं। इसको ही आधार बनाते हुए बहुमत के निर्णय से अलग जाते हुए न्यायमूर्ति बेला त्रिवेदी ने 2004 के ईवी चिन्नैया मामले में सुनाए गए निर्णय को सही बताया, जिसके अनुसार, एससी समुदाय का सजातीय होने के कारण उप-वर्गीकरण नहीं हो सकता। लेकिन मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने बहुमत के साथ ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला देते हुए कहा कि अनुसूचित जातियां एक सजातीय वर्ग नहीं हैं और इसलिए उनका उप-वर्गीकरण अनुच्छेद-14 में निहित समानता के अधिकार का उल्लंघन नहीं करता। दरअसल, आर्थिक व सामाजिक समानता लाने के उद्देश्य से ही आरक्षण की व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लेकिन, इसे लागू हुए इतने वर्षों बाद भी ये उद्देश्य पूरे नहीं हो सके हैं, बल्कि असमानता और बढ़ी ही है। ऐसे में, विकास की दौड़ में पीछे रह गई जातियों को मुख्य धारा में वापस लाने के लिए ओबीसी की तरह अनुसूचित जातियों में भी आरक्षण के भीतर आरक्षण की जरूरत को अदालत ने संविधान अनुरूप माना है, जो जायज भी है। अदालत का फैसला उन राज्यों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगा, जो आरक्षण के बावजूद सीमित प्रतिनिधित्व वाली कुछ अन्य जातियों को भी आरक्षण का फायदा पहुंचाना चाहते हैं। हालांकि जनगणना व जातिगणना के नवीनतम आंकड़ों के अभाव और चार राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों के मद्देनजर इस निर्णय के बाद इंदिरा साहनी फैसले में तय आरक्षण की पचास फीसदी सीमा को रद्द करने के लिए संविधान संशोधन की मांग का सरकार पर दबाव बढ़ सकता है। साथ ही, आरक्षण के विषय की संवेदनशीलता को देखते हुए अब सरकारों को भी काफी सतर्कता बरतनी होगी। न्यायालय का फैसला निस्संदेह महत्वपूर्ण है, पर इसके क्रियान्वयन के लिए जरूरी आंकड़ों को जमा करना जटिल काम है। देखना होगा कि राजनीतिक दल अपनी आकांक्षाओं के मद्देनजर इसका कैसे उपयोग करते हैं।

अग्निवीर का दूसरा पहलू

देश में हर साल 95 लाख युवा स्नातक बनते हैं, जिनमें से ज्यादातर बेरोजगार रहते हैं। एक औसत स्नातक को हर महीने दस से पंद्रह हजार रुपये से ज्यादा नहीं मिलते। अग्निवीर चार साल सेना में काम करने के बाद दूसरी नौकरी पा सकता है और रोजगार के समानांतर पढ़ाई भी कर सकता है।

वीरेंद्र कपूर
लेखक एवं शिक्षाविद

अग्निवीर योजना के पक्ष और विपक्ष में सैकड़ों लेख लिखे गए हैं, यहां तक कि विशेषज्ञ भी भ्रमित हैं। चूंकि नकारात्मक बातें सकारात्मक बातों के मुकाबले ज्यादा फैलती हैं, कुछ राजनीतिक दल इसे गलत ढंग से पेश करते हैं, ताकि जनता को सत्ताधारी व्यवस्था के खिलाफ भड़काया जा सके। संख्या के लिहाज से हमारी सेना सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। पुरानी भर्ती प्रणाली में सेना की भर्ती शाखा भर्ती कार्यालय (बीआरओ) द्वारा की जाती थी, जहां आवेदकों का चयन कुछ खास मानदंडों के आधार पर किया जाता था। मोटे तौर पर ऊंचाई, वजन, छाती की माप के आधार पर स्क्रीनिंग होती थी। उसके बाद शारीरिक फिटनेस की जांच होती थी, जिसमें दौड़ना, पुलअप और संतुलन अभ्यास शामिल थे। छांटे गए उम्मीदवारों को एक लिखित परीक्षा से गुजरना पड़ता था। ज्यादातर सैनिकों (पैदल व अन्य लड़ाकू जवानों) के लिए परीक्षा बहुत कठिन नहीं होती थी। चयन के बाद जवानों को संबंधित शाखा केंद्रों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाता था और प्रशिक्षण की अवधि उसके ट्रेड की आवश्यकता के अनुसार होती थी। यहां तक कि एक ड्राइवर को भी लंबे समय तक प्रशिक्षण दिया जाता था, जिसकी वास्तव में आवश्यकता नहीं थी।

अग्निवीर योजना के बारे में कहा जाता है कि इसके बारे में सशस्त्र बलों से सलाह नहीं ली गई। यानी राजनीतिक नेतृत्व द्वारा इस योजना को रक्षा बलों पर थोपा गया। जबकि वरिष्ठ सेवानिवृत्त सैन्य अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल राज शुक्ला का कहना है कि सेना प्रशिक्षण कमान (एआरटीआरएससी) के सेना कमांडर के रूप में उन्होंने लागू होने से पहले इस योजना पर विस्तार से चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि दुनिया में किसी भी अन्य सेना ने अपने सैनिकों को 23 सप्ताह से अधिक समय तक प्रशिक्षित नहीं किया है और अग्निवीर को छह महीने यानी 24 सप्ताह तक प्रशिक्षित किया गया है। क्या हमें प्रशिक्षण में तीन साल बर्बाद करने की जरूरत है? आप हमेशा समय सीमा को उचित विश्व मानक तक सीमित कर सकते हैं। हमें प्रशिक्षण की गुणवत्ता और कठोरता पर ध्यान देना चाहिए, न कि अवधि पर।

किसी व्यक्ति के लिए पहली नौकरी की तलाश सबसे बड़ी चुनौती होती है। हर नियोक्ता अनुभव प्रमाण पत्र मांगता है। इसलिए, नौकरी चाहने वाला व्यक्ति असमंजस में फंस जाता है, क्योंकि बिना नौकरी के कार्य का अनुभव नहीं हो सकता और बिना कार्य अनुभव के नौकरी नहीं मिल सकती। अग्निवीर योजना का सबसे बड़ा लाभ है 'कार्य अनुभव'। एक शानदार कार्य अनुभव और सैन्य नैतिकता से परिचय, जिसे रुपयों में नहीं मापा जा सकता। यह 'सीखते हुए कमाने' का एक तरीका है। उदाहरण के लिए, इस बार के बजट में इंटर्नशिप योजना की घोषणा की गई है। एक इंटर्न के रूप में अभ्यर्थी को प्रति महीने 5,000 रुपये मिलेंगे और काम करने का अनुभव मिलेगा। यदि कंपनी को आपका काम पसंद आता है, तो आपको वहीं नौकरी मिल सकती है या आप अपने बायोडाटा में इसका उल्लेख करके कहीं और नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं। इंटर्नशिप योजना रोजगार चाहने वाले स्नातकों के लिए है।

अग्निवीर हर लिहाज से बेहतर योजना है। कोई भी सरकार रोजगार पैदा नहीं कर सकती। सभी राजनीतिक दलों को यह बात समझनी चाहिए और हर जगह बाधाएं खड़ी करना और अच्छी योजनाओं को भी विफल करना बंद करना चाहिए। अगर आपके पास कोई बेहतर विचार है, तो उसे संसद में पेश करें। उसे सुनने के लिए सरकार तैयार है। पहले वर्ष में अग्निवीरों को 30,000 रुपये का मासिक पैकेज मिलता है, जिसमें 21,000 रुपये का इन-हैंड वेतन होता है। 9,000 रुपये अग्निवीर की तरफ से कॉर्पस फंड में जमा होता है, और इतनी ही राशि सरकार द्वारा भी इस फंड में जमा की जाती है। इस तरह से प्रभावी रूप से एक अग्निवीर का मासिक वेतन 39,000 रुपये होता है। इसके अतिरिक्त तीनों सेवाओं में लागू जोखिम व कठिनाई भत्ते और तीस दिन की वार्षिक छुट्टी, एलटीसी, कैंटीन सुविधा एवं चिकित्सा आदि की सुविधाएं मिलती हैं।

अगर अग्निवीर उद्यमी बनना चाहते हैं, तो उन्हें बैंक ऋण में प्राथमिकता मिलेगी। अगर अग्निवीर आगे पढ़ना चाहते हैं, तो उन्हें कक्षा 12 के समकक्ष प्रमाणपत्र और आगे की पढ़ाई के लिए पसंद का ब्रिजिंग कोर्स दिया जाएगा। यह मत भूलिए कि ज्यादातर अग्निवीर मात्र 12वीं पास हैं, वे पढ़ाई में बहुत अच्छे नहीं हैं। अग्निवीर को उनकी नियुक्ति अवधि के लिए 48 लाख रुपये का गैर-अंशदायी जीवन बीमा कवर प्रदान किया जाता है। समय के साथ अग्निवीरों का वेतन बढ़ता जाता है और चौथे साल का पैकेज 40,000 रुपये प्रति माह होता है। चार साल की सेवा के बाद 25 फीसदी अग्निवीर को सेना में रखा जाता है, बाकी को अपने घर भेज दिया जाता है, जो दुनिया से जूझने के लिए पूरी तरह आत्मविश्वास से भरे होते हैं। उन्हें एकमुश्त 12 लाख रुपये की कर-मुक्त राशि भी मिलती है। सरकार के लिए लागत (सीटीसी) कंपनी के लिए लागत (सीटीसी) के समान ही है। मुफ्त बोर्डिंग, लॉजिंग, (राशन), यूनिफॉर्म और अन्य चीजों के लिए पैसे खर्च करने पड़ते हैं। इसे मापना कठिन है, लेकिन बचत के मामले में यह बड़ा सहारा होगा। सेना का प्रशिक्षण काफी खर्चीला होता है और अग्निवीर को यह मुफ्त मिलता है।

हमें नहीं भूलना चाहिए कि हर साल देश में 95 लाख युवा स्नातक बनते हैं और उनमें से ज्यादातर बेरोजगार रहते हैं। एक औसत स्नातक को हर महीने दस से पंद्रह हजार रुपये से ज्यादा नहीं मिलते। कोई भत्ता भी नहीं मिलता। चार साल स्नातक करने और चार साल काम करने के बाद भी एक सामान्य व्यक्ति अग्निवीर के बराबर रोजगार पाने की स्थिति में नहीं होता है। अग्निवीर चार साल सेना में काम करने के बाद दूसरी नौकरी पा सकता है और रोजगार करने के समानांतर पढ़ाई भी कर सकता है। अग्निवीर प्रशिक्षित, अनुशासित और कठिन मेहनत करने वाला व्यक्ति बन जाता है। अग्निवीरों को 42 महीने का कार्य अनुभव मिलता है, जो सामान्य स्नातक की तुलना में रोजगार पाने के लिए बेहतर स्थिति में होता है। सेना में उसे नेतृत्व, टीमवर्क और एक विशिष्ट संगठन से जुड़े होने की भावना मिलती है। आज कंपनियां अच्छे अनुशासित कार्यबल की तलाश कर रही हैं। इसलिए अग्निवीर योजना युवाओं का जीवन बदलने वाली योजना है।

edit@amarujala.com

जीवन धारा

सिडनी शेल्डन

सफल होने के लिए आपको मित्रों की आवश्यकता होती है और अत्यधिक सफल होने के लिए आपको शत्रुओं की आवश्यकता होती है। अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको हर खेल में माहिर बनना सीखना होगा।

सफल होने के लिए शत्रु भी जरूरी होते हैं

जीवन एक उपन्यास की तरह है। यह रहस्य से भरा है। जब तक आप पृष्ठ नहीं पलटते, आपको पता नहीं चलता कि आगे क्या होने वाला है। हमेशा के लिए कुछ भी नहीं रहता। मृत्यु लोगों में दूसरा सबसे बड़ा डर है और सार्वजनिक रूप से बोलना पहला डर है। हम जीवन में अच्छाई से दूर भागते हैं और अपने पूरे जीवन भर किसी न किसी समस्या से घिरे रहते हैं। कुछ लोग समस्याओं के बोझ तले आत्महत्या कर लेते हैं। आपके पास दो विकल्प हैं। आप भागते और छिपते रह सकते हैं और अपनी समस्याओं के लिए दुनिया को दोष दे सकते हैं, या आप अपने लिए खड़े हो सकते हैं और महत्वपूर्ण व्यक्ति बनने का निर्णय ले सकते हैं। एक ही तो जीवन है, इसे शिक्षा ग्रहण करके और सुंदर बनाने में ऊर्जा खर्च करें। पुस्तकालयों में वह ऊर्जा संग्रहित होती है, जो कल्पना को ईंधन देती है। वे दुनिया की ओर खिड़कियां खोलते हैं और हमें खोज करने और हासिल करने के लिए प्रेरित करते हैं, और हमारे जीवन की गुणवत्ता को बेहतर बनाने में योगदान देते हैं। पुस्तकालय जीवन को बेहतर बनाते हैं।

अगर आप जीतना चाहते हैं, तो आपको खेल में माहिर बनना सीखना होगा। सफल होने के लिए आपको मित्रों की आवश्यकता होती है और अत्यधिक सफल होने के लिए शत्रुओं की आवश्यकता होती है। आप सूर्य हो, और यदि सूर्य बुझ गया, तो छाया भी मर जाएगी। इसलिए जीवन में आप जो कर रहे हैं, उस पर आपको भरोसा है, तो आपको उसके लिए लड़ना होगा। आपको डटे रहना होगा। जब बादलों के अंदर बिजली चमकती है, तो हम कहते हैं कि वे सिर्फ बादल हैं और अपना ध्यान अगले भोजन, अगले दर्द, अगली सांस, अगले पन्ने पर लगा देते हैं। इसी तरह हम आगे बढ़ते रहते हैं। आप विश्वास रखें। कोई भी व्यक्ति खुश होकर पैदा नहीं होता। हर किसी को अपनी खुशी खुद तैयार करनी होती है। हम में से प्रत्येक व्यक्ति अकेला है, लेकिन हम सभी को एक-दूसरे को आराम और गर्मजोशी देने के लिए एक साथ रहना चाहिए। कभी-कभी ऐसा लगता है, मानो शांति एक सुस्ती है, एक ऐसा कुहासा है, जो मानवजाति को उदासी से भर देती है, केवल युद्ध ही है, जो मनुष्य को जीवन के पूर्ण उल्लास के लिए प्रेरित कर सकता है। सत्य यही है कि दुनिया बहुत सुंदर है। आपको इस सुंदरता को पहचानना होगा। हमारी पृथ्वी में जादू तो है, लेकिन आपको जादूगर बनना होगा और आपको जादू को घटित करना होगा।

अपने भीतर झांकें

सूत्र

जीवन तो एक पतला धागा है और इसे तोड़ने में बस एक सेकंड लगता है। जीवन के इस पतले धागे में आप स्वयं को खोजना चाहते हैं, तो आईने में मत देखिए, क्योंकि वहां केवल एक अजनबी छाया है। स्वयं के भीतर झांकें और दुनिया को देखेंगे, तो सब कुछ सुंदर लगेगा।

दूसरा पहलू

चीन पहला देश है, जो बढ़ती गर्मी और बाढ़ के प्रभाव को कम करने के लिए शहरों को 'स्पंज सिटी' के तौर पर विकसित कर रहा है।

बाढ़ प्रबंधन के लिए कारगर 'स्पंज सिटी'

चीन दुनिया का पहला देश है, जिसने बढ़ती गर्मी और बाढ़ के प्रभाव को कम करने व सतत जल प्रबंधन को बढ़ावा देने के लिए शहरों को 'स्पंज सिटी' के तौर पर विकसित करना शुरू किया है। चीन के दो दर्जन से भी अधिक शहरों को इस रूप में ढाला जा चुका है, जबकि 2030 तक वह अपने 80 फीसदी शहरों को 'स्पंज सिटी' बनाने का लक्ष्य हासिल कर लेगा। यह परियोजना अन्य देशों में भी लोकप्रिय हो रही है। ऑकलैंड, नैरोबी, न्यूयॉर्क, कार्डिफ, टोरंटो जैसे अन्य शहर भी इसके सफल उदाहरण हैं।

सुधीर कुमार

'स्पंज सिटी' शब्द 2013 में चीन के प्रोफेसर कॉंगजियन यू ने गढ़ा था। 2030 तक चीन के 80 फीसदी शहर 'स्पंज सिटी' में बदल जाएंगे।

'स्पंज सिटी' शब्दावली को सर्वप्रथम 2013 में चीन के पीकिंग विश्वविद्यालय के प्रोफेसर कॉंगजियन यू ने गढ़ा था। इससे उनका तात्पर्य उन शहरों से था, जो बारिश के पानी को अवशोषित करने के लिए प्रकृति के साथ काम करते हैं। 'स्पंज सिटी' बाढ़ प्रबंधन व पारिस्थितिक बुनियादी ढांचे तथा जल निकासी प्रणालियों को मजबूत करने के लिए एक नया शहरी निर्माण मॉडल है। यह जलवायु परिवर्तन से निपटने का एक प्रकृति आधारित समाधान है, जिसमें वर्षा जल का समुचित संचयन, जल पुनर्भरण और शहरों को डूबने से बचाने के लिए पर्याप्त संख्या में हरित आवरण विकसित किए जाते हैं। इस विधि के तहत, वर्षा जल को नालियों के जरिये शहर से बाहर पहुंचाने के बजाय पर्याप्त जगह व समय देकर मिट्टी में उसके अवशोषण को सुनिश्चित किया जाता है। यह विधि भारी वर्षा से शहर को डूबने से बचाने के साथ-साथ गर्मी के दिनों में शहर के तापमान को भी कम करती है। शहरों में उद्यानों, झीलों, तालाबों का विकास और जीर्णोद्धार भारी वर्षा के दौरान पानी को सोख लेता है और सूखा पड़ने पर भूजल स्तर में वृद्धि कर शहरवासियों को जल-किल्लत से बचाता है। इस तरह स्पंज सिटी अत्यधिक वर्षा और अत्यधिक गर्मी दोनों ही स्थितियों में शहरवासियों की सुरक्षा करता है। साथ ही, शहर को बाढ़, सूखा, गर्म द्वीप बनने, मरुस्थलीकरण और भूस्खलन जैसी आपदाओं से भी बचाते हैं। ऐसे शहर अपने हरित आवरण से नागरिकों को शारीरिक और मानसिक रूप से सेहतमंद बनाते हैं।

तेजी से शहरीकृत होते भारत में भी शहरों को 'स्पंज सिटी' के तर्ज पर विकसित करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, 2030 और 2035 में देश की क्रमशः 54.37 और 67.5 फीसदी आबादी शहरों में निवास करेगी।

तेजी से शहरीकृत होते भारत में भी शहरों को 'स्पंज सिटी' के तर्ज पर विकसित करने की जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र के अनुमान के मुताबिक, 2030 और 2035 में देश की क्रमशः 54.37 और 67.5 फीसदी आबादी शहरों में निवास करेगी। 'स्पंज सिटी' परियोजना के तहत इन्हीं हरित संरचनाओं को पुनर्जीवित किया जा रहा है। यह तकनीक पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करती है।

आंकड़े

डिजिटल भारत

भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता लगातार बढ़ रहे हैं। मौजूदा आंकड़े बताते हैं भारत डिजिटलीकरण की ओर तेजी से बढ़ रहा है।

यूपीआई	42.40
सोशल मीडिया	46.70
स्मार्टफोन	75.00
इंटरनेट	95.40
आधार	138.00

आंकड़े उपयोगकर्ताओं के करोड़ में हैं। स्रोत : TRAI, Statista, RBI

कालयवन को वरदान प्राप्त था कि उसे अस्त्र-शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। उसने मथुरा पर आक्रमण किया, तो श्रीकृष्ण वहां पहुंच गए, जहां मुचुकुंद सो रहे थे।

कृष्ण ने मुचुकुंद से मरवाया कालयवन

एक बार असुरों ने देवताओं पर धावा बोल दिया। देवताओं ने अपनी रक्षा के लिए महाराज मुचुकुंद से आग्रह किया। कई वर्षों तक मुचुकुंद ने असुरों से देवताओं की रक्षा की। इसके बाद भगवान शिव के पुत्र कार्तिकेय देवताओं के सेनापति बन गए। इंद्र ने मुचुकुंद से कहा कि आपने हमारी रक्षा कर बड़ी कृपा की है। आप हम से मोक्ष को छोड़कर कोई भी वर मांग सकते हैं, क्योंकि हमारे पास मोक्ष प्रदान करने की शक्ति नहीं है।

मुचुकुंद ने कहा, 'बहुत थक गया हूं, इसलिए खूब सोना चाहता हूं'। इंद्र ने कहा, 'ऐसा ही होगा और जो भी आपकी निद्रा तुड़वाएगा, वह आपके देखते ही भस्म हो जाएगा'। मुचुकुंद को सोते हुए अनेक वर्ष बीत गए और द्वापर युग आ गया। जरासंध के कहने पर कालयवन नाम के राक्षस ने मथुरा पर आक्रमण कर दिया। वह श्रीकृष्ण को मारना चाहता था। दरअसल, कालयवन के पिता ऋषि शेशिरायण को भगवान शिव ने वरदान दिया था कि आपके पुत्र को अस्त्र-शस्त्र या कोई भी योद्धा नहीं मार सकेगा। भगवान श्रीकृष्ण भागते हुए धौलपुर के पास उस गुफा में पहुंचे, जहां मुचुकुंद सो रहे थे। श्रीकृष्ण ने अपना पीतांबर मुचुकुंद पर डाल दिया। कालयवन ने जाकर जैसे ही मुचुकुंद के ऊपर पीतांबर देखकर जगाया, तो उनकी नजर पड़ते ही कालयवन भस्म हो गया। इसके बाद श्रीकृष्ण ने मुचुकुंद को अपनी भक्ति का वरदान दिया।

अंतर्यात्रा
संकलित

अमर उजाला

पुराने पन्नों से — 21 जनवरी, 1957

अरब के नेताओं ने ठुकरा दी अमेरिका की योजना

बाहरी शक्ति को रिक्त स्थान न भरने दिया जायगा
इसे पश्चिमी के सैनिक गुटों से अलग रहे
पश्चिम की ओर से कोई भी दबाव न पड़ेगा
मिस्र, सऊदी अरब, जॉर्डन और सीरिया के नेताओं ने अपनी दो दिन की मंत्रणा के बाद यह तय किया है कि पश्चिम एशिया के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावर ने जो योजना तैयार की है, वह उन्हें स्वीकार नहीं है।

सहरिया आदिवासियों की भी सुनें

सहरिया आदिवासियों में प्रवासी मजदूरी पर निर्भरता कम नहीं हो रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर आजीविका का आधार बहुत कमजोर है।

भारत डोगरा | विषमता

आदिवासी कल्याण योजनाओं की बहुत चर्चा रही है और इस संदर्भ में सहरिया आदिवासियों का भी नाम आता रहा है, लेकिन झांसी जिले (उत्तर प्रदेश) के बबीना खंड में स्थित दूर-दूर की दो सहरिया बस्तियों में जाकर तो यही लगा कि यहां प्रवासी मजदूरी पर निर्भरता कम होने का नाम नहीं ले रही है, क्योंकि स्थानीय स्तर पर आजीविका का आधार बहुत कमजोर है।

मथुरापुर गांव की सहरिया बस्ती के लोगों ने बताया कि ज्यादातर परिवार भूमिहीन हैं व बहुत थोड़े से परिवारों के पास कृषि-भूमि है, जो बहुत कम है। सरकारी आवास योजना के अंतर्गत कुछ परिवारों के पक्के घर बन गए हैं, शेष पुराने कच्चे घरों में ही रहते हैं। जिनका हाल में पक्का घर बना है, वह भी पूरी तरह सरकारी सहायता से नहीं बन पाया। इसके लिए उन्हें कुछ कर्ज भी लेना पड़ा और वह भी पांच प्रतिशत प्रतिमाह की ऊंची ब्याज दर पर। जल के लिए सरकार ने पहपलाइन तो बिछा दी है, पर इन नलों और पाइप में पानी अब तक नहीं आया है। अतः पहले के दो हैंडपंपों पर ही पूरी बस्ती निर्भर है। भीषण गर्मी के दिनों में हैंडपंप जल्दी ही हांफने लगते हैं। पानी की कमी बनी रहती है और बहुत-सा समय पानी का इंतजाम करने में ही चला जाता है। मनरेगा में हाल के समय में बहुत ही कम रोजगार मिल सका है।

इन स्थितियों में ज्यादातर परिवार अपना पेट भरने के लिए प्रवासी मजदूर बनने को मजबूर हैं। महिलाओं ने बताया कि वहां जाने पर कठिनाइयां बहुत बढ़ जाती हैं, पन्नी लगाकर रहना पड़ता है। धूप, वर्षा, सर्दी सभी की मार अधिक सहनी पड़ती है, पर मजबूरी है कि जाना ही पड़ता है।

सेमरिया गांव की एक सहरिया बस्ती में महिलाओं ने बताया कि कभी-कभी तो प्रवासी मजदूरी में मेहनत करने पर जो मजदूरी मिलनी होती है, उसमें से कटौती कर ली जाती है। ऐसा भी हुआ है कि मजदूरी के बिना ही लौटना पड़ा। बाहर जाने पर उनकी स्थिति कमजोर होती है और कई बार उन्हें मजदूरी के मामले में ठगा जाता है। उन्होंने बताया कि आवास थोड़े से बने हैं, पर मनरेगा में काम नहीं मिल रहा है। गांव में बने रहें, तो गुजारा नहीं होता है। उन्होंने कहा कि प्रवासी मजदूरी करने से बच्चों की शिक्षा की क्षति तो होती है, पर फिर भी हमें जाना पड़ता है।

इन महिलाओं ने बताया कि राशन तो फिर भी ठीक से मिल जाता है। पर आंगनवाड़ी से पौष्टिक आहार बहुत कम मिल पाता है। अपनी बस्ती की एक विशेष समस्या का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उनके घरों के बहुत पास से हाईटेंशन लाइन गुजर रही है और उनकी सुरक्षा का कोई उपाय नहीं है। इनमें बहुत करंट होता है, जो उन्हें प्रभावित करता है। कुछ समय पहले तार गिरने से उनके पांच घर जल गए। इसके बाद कुछ अधिकारी, तो गांव में आए, लेकिन प्रभावित परिवारों को कोई मुआवजा अब तक नहीं दिया गया है। वे चाहते हैं कि इस बारे में संबंधित विभाग शीघ्र कार्यवाही कर उनको मुआवजा दे और भविष्य के लिए भी सुरक्षा व्यवस्था की जाए। तारों के नीचे सुरक्षा जाल लग सकता है पर यह नहीं लगा है, उन्होंने बताया।

इन दोनों बस्तियों की महिलाओं ने बाहरी समस्याओं की ओर ध्यान आकर्षित किया, वहां उन्होंने यह भी एक मत से स्वीकार किया कि पुरुषों द्वारा शराब अधिक पीने की प्रवृत्ति उनके समुदाय के लिए सबसे बड़ी आंतरिक समस्या बन गई है। इसका बच्चों पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। कुछ महिलाओं ने बहुत ही दुखी मन से बताया कि पहले इतनी मेहनत से, इतनी कठिनाइयों के बीच, जो थोड़ी कमाई होती, वह भी परिवार की भलाई पर खर्च करने के बजाय दारू पर बर्बाद कर दी जाती है। जब महिलाएं इस पर आपत्ति करती हैं, तो उनकी मार-पिटाई भी होती है, घरेलू हिंसा बढ़ती है। कुछ महिलाओं ने कहा कि शराब तो महिलाओं की सबसे बड़ी दुश्मन है, इसे तो जरूर बंद होना चाहिए।

इस तरह सहरिया समुदाय जहां कई तरह की विषमता और अन्याय से त्रस्त है और उसे समाज के हाशिये पर धकेल दिया गया है। वहीं, दूसरी ओर उनकी कुछ आंतरिक समस्याएं भी हैं, जिन्हें समाज सुधार के प्रयास से दूर किया जा सकता है। सहरिया समुदाय को न्याय भी चाहिए और समाज-सुधार भी। उल्लेखनीय है कि सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश के ग्वालियर-चंबल संभाग में बड़े स्तर पर पाई जाती है। यह जनजाति राजस्थान के बारन जिले में भी मिलती है। वहीं मध्य प्रदेश से सटे उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी सहरिया आदिवासी बसे हुए हैं। सहरिया लोग खुद को भील आदिवासियों के सहोदर भाई मानते हैं।

दैनिक जागरण

समस्या को अनदेखा करने से वह और विकराल हो जाती है

एनटीए की कार्यप्रणाली

सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल कालेजों में प्रवेश की परीक्षा-नीट के मामले में अपने विस्तृत निर्णय में इस परीक्षा के साथ अन्य अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्था नेशनल टेस्टिंग एजेंसी अर्थात एनटीए को कई दिशानिर्देश देते हुए उसे अपनी कार्यप्रणाली सुधारने की जो नसीहत दी, उस पर हर हाल में अमल होना चाहिए। इसलिए होना चाहिए, क्योंकि उसके कामकाज को लेकर गंभीर सवाल उठने के साथ ही उसकी प्रतिष्ठा को क्षति भी पहुंची है। यह ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट ने नीट में गड़बड़ियों के चलते उसे दोबारा कराए जाने की मांग इस आधार पर ठुकरा दी कि परीक्षा के आयोजन में गड़बड़ी केवल पटना और हजारीबाग में हुई थी और उसका राष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि एनटीए की साख को चोट न पहुंची हो। इससे संतुष्ट नहीं हुआ जा सकता कि नीट में गड़बड़ी के आरोपों के बीच सरकार ने एनटीए प्रमुख को हटा दिया था और इस संस्था की कार्यप्रणाली में सुधार के लिए एक समिति गठित कर दी थी, क्योंकि यह सब बहुत पहले होना चाहिए था। ध्यान रहे यह पहली बार नहीं है, जब एनटीए की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठे हों। जब नीट का मामला चर्चा में था, तभी एनटीए को कम से कम तीन परीक्षाओं को इस अंदेशे के चलते टालना पड़ा था कि कहीं उनके प्रश्नपत्र लीक न हो गए हों।

यह अच्छा हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ने एनटीए के कामकाज में सुधार के लिए गठित समिति का विस्तार किया। आशा की जाती है कि एनटीए इस समिति के सुझावों पर अमल करके परीक्षाओं की सुचिता सुनिश्चित करने में समर्थ होगी। यह तभी संभव हो पाएगा, जब वह अपनी कमियों को दूर करने के लिए कमर कसेगी। इस एजेंसी की ओर से कराई जाने वाली परीक्षाओं में उन्नत तकनीक का उपयोग बढ़ाना होगा और परीक्षाएं कंप्यूटर से ही करानी होंगी, लेकिन ऐसा करते समय इसके प्रति सतर्क रहना होगा कि उसके तकनीकी तंत्र में सेंध न लगने पाए। इसके अतिरिक्त उसे प्रश्नपत्रों के कई सेट तैयार करने होंगे, ताकि यदि कहीं कोई गड़बड़ी हो जाए तो उससे देश भर की परीक्षा प्रभावित न होने पाए। समझना कठिन है कि सूचना तकनीक में उन्नत समझा जाने वाला देश अपनी प्रतियोगी परीक्षाओं के आयोजन में उसका सही उपयोग क्यों नहीं कर पा रहा है? वास्तव में एनटीए को अपनी कार्यप्रणाली सुधार कर परीक्षाओं का आयोजन इस तरह करना होगा, जिससे वह प्रतियोगी परीक्षाएं कराने वाली अन्य संस्थाओं के समक्ष उदाहरण पेश कर सके और वे उससे कुछ सीख सकें। पिछले कुछ वर्षों में अनेक प्रतियोगी परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक हुए हैं। इनमें कई परीक्षाएं राज्य सरकारों की संस्थाओं द्वारा कराई गई थीं। इन परीक्षाओं के प्रश्नपत्र लीक होने से लाखों छात्र प्रभावित हुए। उनके समय के साथ संसाधन की बर्बादी हुई और उनका सरकारी तंत्र पर भरोसा भी डिगा।

सावधान रहकर बचाएं जान

अब यह तो कह नहीं सकते कि बिहार में आमलोगों को वज्रपात से बचने के उपायों की जानकारी नहीं है, क्योंकि संचार के प्रायः सभी माध्यमों से यह जानकारी लगातार दी जाती रही है कि वज्रपात से कैसे बचें। मुख्य सलाह यह कि ऐसे समय में घर से बाहर न निकलें, पेड़ के नीचे या खुली जगह में न रुकें। किसी छतदार मकान के नीचे शरण लें। इसके अलावा भी बचाव के ढेर सारे उपाय बताए जाते रहे हैं। जरा वज्रपात से होने वाली मौतों पर नजर डालिए। अधिसंख्य मौतें खेत में काम करने और पेड़ के नीचे खड़े होने के दौरान बिजली गिरने से हो रही हैं। इन दोनों से बचा जा सकता है। इसलिए कि वर्षा के बाद भी खेतों में काम हो सकता है। बादलों की प्रकृति को देखकर घर से बाहर निकला जा सकता है। आजकल मुख्य सड़क के किनारे ढेर सारे पक्के भवनों का निर्माण हो रहा है। उसमें शरण लेकर जान बचाई जा सकती है। चेताकनी के तौर पर जो सलाह दी जाती है, उसमें यह भी बताया जाता है कि निर्जन स्थलों पर कैसे वज्रपात से अपनी जान बचाई जा सकती है। कुल मिलाकर सावधान रहकर कम से कम नब्बे प्रतिशत लोग वज्रपात से बच सकते हैं। वज्रपात से होने वाली मौतें आपदा की श्रेणी में घोषित की गई हैं। वज्रपात से मृत्यु की स्थिति में राज्य सरकार मृतक के स्वजन को चार लाख रुपये मुआवजा देती है। किसी कमाऊ सदस्य के गुजर जाने के एवज में दी गई यह राशि क्षति की भरपाई नहीं कर सकती है। क्योंकि इसमें सिर्फ कमाऊ हाथ ही नहीं चला जाता है, बल्कि रिश्ते की मौत भी होती है। मरने वाला किसी का भाई, पिता, पति व बेटा भी होता है। इस भावनात्मक क्षति की भरपाई किसी भी रकम से नहीं हो सकती है। इसलिए सावधानी ही वज्रपात से बचने का पहला और अंतिम उपाय है। इसलिए जब कभी घर से निकलें सलाह और बादलों को प्रवृत्ति पर गौर करें।

पक्षपाती अल्पसंख्यकवाद के दुष्परिणाम

शंकर शरण

संविधान केवल पश्चिमी अर्थ वाले 'रिलीजन' का नोटिस लेता है। देश की सबसे महान और प्रसिद्ध धारणा 'धर्म' उससे नदारद है

देश में रह-रहकर ऐसे प्रसंग घटते रहते हैं, जो हिंदू-मुस्लिम संबंधों पर विचार करने को बाध्य करते हैं, जैसे हाल में कांवड़ यात्रियों के मार्ग में दुकानदारों के नाम लिखने का आदेश। हिंदू-मुस्लिम संबंधों के प्रति स्वतंत्र भारत की नीति किस तरह दोहरापन लिए रही है, इसका ही उदाहरण है कांवड़ यात्रियों को भोजन भावना पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला। हमारे न्यायालय अन्य समुदाय के लिए हलाल भोजन शर्तों को उचित समझते हैं, बल्कि दूसरों पर थोपने की भी अनदेखी होती है, पर वही न्यायालय हिंदुओं के सात्विक भोजन आग्रह पर नजर टेढ़ी करते हैं। यह केवल भोजन की बात नहीं। दीवाली, जन्माष्टमी, दशहरा जैसे त्योहारों से लेकर अमरनाथ यात्रा और सबरीमाला जैसे मंदिरों की रीतियों पर भी कभी पर्यावरण तो कभी जीव-रक्षा या स्वास्थ्य के नाम पर न्यायिक डंडा चलाता रहता है, जबकि उन्हीं तर्कों से इस्लामी रिवाजों पर प्रश्न नहीं उठता। एक न्यायाधीश ने जन्माष्टमी पर मटकी फोड़ने की ऊंचाई पर प्रतिबंध के मामले में कटाक्ष करते हुए कहा था, 'क्या कृष्ण भी ऐसा सर्कस करते थे।' किसी गैर-हिंदू रीतियों पर वह कुछ नहीं कहते, चाहे मानवीय संवेदनाओं से वे कितनी भी अनुचित क्यों न लगें। यह दोहरा व्यवहार राज्यतंत्र के तीनों अंगों और मीडिया एवं अकादमिकों के बड़े हिस्से में भी है। निर्मल वर्मा के शब्दों में ऐसा रवैया 'चुनी हुई चुप्पी और चुना हुआ शोर' स्वतंत्र भारत की लज्जाजनक विशेषता बन चुकी है। ऐसा ब्रिटिश राज में भी नहीं था। कुरीतियों पर विराम के मामले में ब्रिटिश शासक सांप्रदायिक भेद नहीं करते थे। यदि अंग्रेजों ने बंगाल में सती-प्रथा को खत्म किया तो शरीयत के अनेक कायदों को भी बंद किया था। उन्होंने मिशनरियों को भी सख्ती से नियंत्रण में रखा। लगभग पूरे ब्रिटिश काल में नागरिक कानून हिंदुओं-मुस्लिमों पर एक जैसे रहे थे। 1937 में मुस्लिम पर्सनल ला बनने में कांग्रेस और मुस्लिम लीग की प्रतिद्वंद्विता की भूमिका थी, जब अंग्रेजों का जाना दिखने लगा।

ब्रिटिश राज में पंथ और संस्कृति के क्षेत्र में कोई शासकीय दखल नहीं था। सभी समुदाय अपनी रुचि की शिक्षा लेने, संस्थान बनाने, रीति-रिवाज और त्योहार आदि अपनी परंपरा से मनाने के लिए मुक्त थे। स्वतंत्र भारत के संविधान ने ही दो प्रकार के नागरिक बनाए: अल्पसंख्यक और गैर-अल्पसंख्यक। अल्पसंख्यकों को दोहरे अधिकार मिल गए-एक नागरिक के रूप में, दूसरे अल्पसंख्यक के रूप में। जबकि हिंदुओं को मात्र नागरिक के रूप में अधिकार हैं। हिंदू के रूप में उसे संविधान कोई अधिकार नहीं देता। इस प्रकार, जहां मुस्लिमों और ईसाइयों को नागरिक के रूप में वे सभी अधिकार हासिल हैं, जो हिंदुओं को हैं। वहीं उन्हें अल्पसंख्यक के रूप में अतिरिक्त विशिष्ट अधिकार मिल गए हैं, जो हिंदुओं को नहीं हैं। संविधान के अनुच्छेद 25 से 31 तक यही व्यवस्था है। यह आज इतना विकृत रूप ले चुका है, जिसकी संविधान निर्माताओं ने कल्पना भी नहीं की थी, पर उन्होंने ही संविधान में ऐसे प्रविधान बनाए, जो अनजाने ही हिंदुओं को हीन बना देते थे।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25(1) 'रिलीजन' का वही अर्थ लेता है, जो ईसाइयत और इस्लाम की मान्यताओं के अनुरूप है। रिलीजन और धर्म समानार्थी नहीं, यह संविधान निर्माता भी जानते थे। इसीलिए बाद में जोड़े गए सेक्युलरिज्म को भी हिंदी में अधिकारिक रूप से पंथनिरपेक्षता कहा गया, न कि धर्मनिरपेक्षता। हिंदू परंपरा में धर्म पर चलना और उसकी रक्षा करना रहा है। उसे कोई फेथ मानना और दूसरों से येन-केन वही मनवाना, सबको अपने घेरे में लाना, यह सब हिंदू धर्म के लिए विजातीय है, लेकिन संविधान में हिंदुओं को अपने धर्म की रक्षा करने का अधिकार नहीं दिया गया। इस अनुच्छेद के अनुरूप अपना रिलीजन फैलाना मिशनरियों, तब्लीगियों का तो मौलिक अधिकार है, किंतु हिंदुओं को संगठित मतांतरणकारियों से भी अपने लोगों को बचाने का अधिकार नहीं है। ऐसे प्रयासों को अल्पसंख्यकों के मौलिक अधिकार का हनन बताया जाता है, क्योंकि संविधान केवल पश्चिमी अर्थ वाले 'रिलीजन' का नोटिस लेता है। भारत की सबसे महान और प्रसिद्ध धारणा 'धर्म' उससे नदारद है। रिलीजन की सारा स्थान ठेकर धर्म का बिलौप कर दिया गया है। संविधान सभा में आचार्य रघुवीर ने इस पर आपत्ति की थी, लेकिन धर्म को संविधान में स्थान नहीं मिला।

आज हिंदुओं के मामले में संविधान के अनुच्छेद 26 (बी) की कोई परवाह नहीं की जाती। चर्च और मस्जिदें तो केवल उनके अनुयायियों की ही इच्छा से चलती हैं, लेकिन हिंदू मंदिरों पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अपना सेक्युलरवाद थोपते हुए पाबंदियां ठोकती रहती हैं। यह अनुच्छेद 26 (बी) की भावना के विरुद्ध है। शिक्षा, प्रशासन, विवाह, पारिवारिक कानून आदि विषयों में राज्य तंत्र के तीनों अंग इस्लामी दावों को तो मंजूर करते हैं, लेकिन हिंदू परंपराओं, रीति-रिवाजों पर आधुनिक बौद्धिकता की कुल्हाड़ी चलाते हैं। प्रतिक्रियास्वरूप अक्सर देश में असंतोष और राजनीतिक उथलपुथल होती है, पर हमारे शासक, बौद्धिक और न्यायिक वर्गों ने उससे कुछ न सीखा। वे अपना पक्षपाती अल्पसंख्यकवाद और एकतरफा सेक्युलरवाद यथावत चला रहे हैं। इस दोहरेपन से हिंदू-मुस्लिम संबंधों में जो ईर्ष्या, संदेह और दुराव बढ़ता है, उसकी उन्हें कोई परवाह नहीं। विभिन्न दल और देसी-विदेशी वर्ग इस असहज स्थिति का अपने-अपने स्वार्थ साधने में इस्तेमाल करते हैं। इसका सबसे ज्वलंत पक्ष संसद है, जिसमें ऐसे मुद्दों, घटनाओं पर निष्पक्ष विचार नहीं होता। सब कुछ पार्टीबाजी की भेंट चढ़ जाता है। चाहे किसी क्षेत्र से पूरी हिंदू आबादी को आतंकित, अपमानित कर भगा दिया गया हो, उस पर राज्य तंत्र के तीनों अंगों में जिम्मेदारी का अभाव रहा है। वे एक-दूसरे पर जिम्मेदारी डालते, कतराते, बचते हैं अथवा ऐसे पक्षपाती फैसले करते हैं, जिसमें उन्हें स्वयं कोई चोट झेलने का खतरा कम रहे। ऐसा विकृत सेक्युलरिज्म या चापलूस अल्पसंख्यकवाद ब्रिटिश राज में नहीं था। फलतः तब हिंदू-मुस्लिम संबंध अधिक सहज थे। प्रेमचंद की कहानियों में भी इसकी झलक दिखती है। चूंकि स्वतंत्र भारत में सामुदायिक भेदभाव की राजनीति बनती-बढ़ती गई, इसलिए सांप्रदायिक ईर्ष्या-द्वेष को ईंधन मिलता रहा है।

(लेखक राजनीतिशास्त्र के प्रोफेसर एवं वरिष्ठ स्तंभकार हैं)

response@jagran.com

अवधेश राजपूत

क्वाड को लेकर बढ़ती अनिश्चितता

ऋषि गुप्ता

यदि अमेरिकी सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो संभव है कि अमेरिका क्वाड को पर्याप्त महत्व न दे

विदेश मंत्री एस. जयशंकर बीते दिनों क्वाड की बैठक में शामिल होने के लिए टोक्यो गए थे। इससे पूर्व इस समूह की बैठक दस महीने पहले न्यूयार्क में हुई थी। भू-राजनीतिक परिदृश्य पर हो रहे परिवर्तनों के संदर्भ में टोक्यो में हुई बैठक खासी महत्वपूर्ण थी। विशेषकर हिंद-प्रशांत क्षेत्र को लेकर, जहां चीन फिलीपींस जैसे देश को दक्षिण-चीन सागर में दबाने और ताइवान की स्वायत्तता पर निरंतर आघात करने की धमकी देता आ रहा है। ऐसे माहौल में विश्व की चार बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं का हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति और नियम आधारित व्यवस्था के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दर्शाना काफी मायने रखता है। क्वाड के माध्यम से अंतरराष्ट्रीय नियमों की बहाली के साथ वैश्विक आर्थिक वृद्धि सुनिश्चित करने के लिए प्रमुख चुनौतियों का सामना करने और आपूर्ति श्रृंखला को सुरक्षित बनाने पर ध्यान दिया जा रहा है। इसके साथ ही क्वाड का उद्देश्य भरोसेमंद और पारदर्शी डिजिटल साझेदारी को बढ़ावा देने की जरूरत पर ध्यान देना भी है, ताकि संकट के समय एक साझा समाधान निकाला जा सके। आज के विश्व में समुद्री मार्ग विश्व व्यापार, डिजिटल बुनियादी ढांचे, सामरिक बढ़त और दुर्लभ खनिजों की दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण हैं। चूंकि चीन ऐसे तमाम क्षेत्रों में अपना अधिकार जताता रहा है, इसलिए क्वाड सदस्य देशों का एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध हिंद-प्रशांत क्षेत्र सुनिश्चित करने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी है। खास बात यह है कि ये चारों देश एक लोकतांत्रिक सूत्र में बंधे हैं और विश्व शांति पर समान विचारधारा रखते हैं और वे साथ मिलकर चीन की विघटनकारी, आक्रामक और विस्तारवादी शक्ति के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं।

अपनी प्रकृति एवं स्वरूप में क्वाड बुनियादी रूप से एक सामरिक मोर्चा न होकर आर्थिक सहयोग, क्षेत्रीय और समुद्री सुरक्षा सहयोग, प्रौद्योगिकी सहयोग के साथ लोकतांत्रिक मूल्यों के समर्थन का एक मंच है, लेकिन चीन के क्षेत्रीय प्रभाव को रोकने का यह अप्रत्यक्ष प्रयास बीजिंग को रास नहीं आता। अपने बयानों में चीन का नाम न लेना क्वाड का एक रणनीतिक निर्णय जरूर माना जा सकता है, लेकिन चीन की इसकी उपस्थिति का अखरना यही दर्शाता है कि उसे अपनी विघटनकारी और आक्रामक नीतियों का अहसास है। टोक्यो में क्वाड की बैठक के दौरान जयशंकर का कहना था कि 'यह कोई बातचीत की दुकान नहीं, बल्कि एक मंच है जो व्यावहारिक परिणाम उत्पन्न करता है।' उनका बयान न केवल क्वाड की एक समूह के रूप में मजबूती, बल्कि चारों सदस्य देशों भारत, अमेरिका, आस्ट्रेलिया और जापान का चीन की नीतियों के खिलाफ साथ खड़ा भी होना दर्शाता है।

पिछले सात वर्षों में क्वाड एक मजबूत पहल के तौर पर उभरा है और ऐसे मुद्दों पर साथ आया है, जो भविष्य में चिंता का सबब बन सकते हैं। टोक्यो की बैठक का एक खास मुद्दा समुद्र के नीचे बिछे डिजिटल संचार केबलों से संबंधित रहा। ऐसा माना जा रहा है कि चीन बैश्विक डिजिटल बुनियादी ढांचे को बाधित करने के लिए युद्ध रणनीति का उपयोग कर रहा है। अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियों ने चिंता जताई है कि चीन इन केबलों में सेंध लगाकर अपनी तकनीक का इस्तेमाल करते हुए व्यक्तिगत डाटा से लेकर बौद्धिक संपदा और गोपनीय सैन्य खुफिया जानकारी चुरा सकता है। विश्व के करीब 95 प्रतिशत डाटा की आवाजाही इन्हीं केबलों के माध्यम से होती है। निश्चित रूप से यह एक बड़ी चिंता का विषय है। अगर भविष्य में हिंद-प्रशांत क्षेत्र में किसी भी तरह के युद्ध की स्थिति बनी तो चीन इन केबलों को काटकर संचार बाधित करने का भी प्रयास कर सकता है। ऐसे में यह आवश्यक है कि हिंद-प्रशांत क्षेत्र में क्वाड देश आपसी सहयोग के साथ ऐसी समस्याओं का समाधान निकालें।

तमाम स्तरों पर बात आगे बढ़ने के बावजूद इस वास्तविकता को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता कि कुछ स्पष्ट रणनीतियों के अभाव में क्वाड अनिश्चितता की ओर बढ़ रहा है। क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्षों की आखिरी बैठक जापान के हिरोशिमा शहर में मई 2023 में हुई थी और आगामी बैठक का इस वर्ष जनवरी में होना तय था, लेकिन राष्ट्रपति बाइडन की अनुपलब्धता के चलते यह नहीं हो पाई। हालांकि अमेरिकी विदेश विभाग के प्रवक्ता ने हाल में हुई प्रेस वार्ता में राष्ट्रपति बाइडन की क्वाड नेताओं की बैठक के प्रति प्रतिबद्धता की बात तो कही, लेकिन कोई निश्चित तारीख भी नहीं बताई। राष्ट्रपति बाइडन के स्वास्थ्य और अमेरिका में हो रहे चुनावों को देखते हुए इस वर्ष भी बैठक मुश्किल दिखती है। इस बीच अच्छी बात यही है कि समूह की अन्य बैठकों से निरंतरता बनी हुई है, लेकिन शीर्ष नेताओं का मिलना इस समूह की प्रतिबद्धताओं को और मजबूती प्रदान करेगा।

क्वाड का भविष्य बड़ी हद तक अमेरिकी चुनाव परिणामों पर भी निर्भर करेगा। यदि अमेरिकी सत्ता में डोनाल्ड ट्रंप की वापसी होती है तो संभव है कि अमेरिका इससे कुछ पीछे हटे, क्योंकि ट्रंप बहुपक्षीय सक्रियता में बहुत ज्यादा विश्वास नहीं करते और अक्सर उन्होंने ऐसे मंचों को लेकर नकारात्मक टीका-टिप्पणियां ही की हैं। ट्रंप का 'अमेरिका प्रथम' का नारा अमेरिका को हर क्षेत्र में पहले रखना चाहेगा और ऐसे में हो सकता है कि क्वाड देशों के साथ सामूहिक बराबरी ट्रंप की रणनीतिक प्राथमिकता न रहे। ऐसे में क्वाड के भविष्य पर सवालिया निशान लग सकता है। यदि इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न होतीं हैं तो भारत के पास एक सुनहरा अवसर होगा कि वह क्वाड समूह का नेतृत्व करे और नई ऊर्जा के संचार के साथ क्षेत्रीय पटल पर अपनी प्रतिबद्धताओं की मुखरता से पैरवी करे।

(लेखक एशिया सोसायटी पालिसी इंस्टीट्यूट, दिल्ली में सहायक निदेशक हैं)

response@jagran.com

ऊर्जा

प्रत्यंचा

किसी भी धनुर्धर के लिए धनुष की प्रत्यंचा लक्ष्य संधान के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। प्रत्यंचा चढ़ाने के कौशल से ही उसका तीर सटीक निशाने पर लगता है। प्रत्यंचा का यह सामान्य सिद्धांत जीवन में भी उसी प्रकार से लागू होता है। जैसे धनुष की प्रत्यंचा तीर को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण होती है, वैसे ही जीवन में हमारे लक्ष्य को पाने के लिए अनुशासन का होना आवश्यक होता है। यह कहना गलत नहीं होगा कि जीवन के लक्ष्य को हम अनुशासन की प्रत्यंचा से ही साध सकते हैं।

आज के वर्तमान समय में मनुष्य अपने जीवन रूपी धनुष की प्रत्यंचा कसना ही भूल चुका है। आज अगर हमारे जीवन का तीर लक्ष्य से चूकता है तो हम या तो तीर-धनुष को कोसने लगते हैं या भाग्य को। जबकि न तो इसमें तीर-धनुष की गलती होती है और न ही भाग्य की। लक्ष्य से चूकने का कारण यह होता है कि हमने अपने जीवन रूपी धनुष की प्रत्यंचा को ही ढीला छोड़ दिया होता है। यानी हम अनुशासित और अपने लक्ष्य को लेकर दृढ़ नहीं होते हैं। यही कारण होता है कि न तो हमारा तीर उस तेजी से इच्छित दूरी को तय कर पाता है और न ही लक्ष्य को छू पाता है। अंत में हम हार मान लेते हैं और अपनी असफलता का सारा दोष किसी बिंदु या परिस्थिति पर मढ़ देते हैं ताकि हमारे पास असफलता का एक जवाब हो।

वस्तुतः कोई भी लक्ष्य भेदन एक तपस्या है। धनुष की प्रत्यंचा उस तपस्या का केंद्र है, जिससे लक्ष्य की परिधि के किसी भी बिंदु को छूआ जा सकता है। लक्ष्य भेदन की कामना रखने वाले मनुष्य को एक संकल्प लेकर अनुशासन रूपी डोर को अपने जीवन रूपी धनुष के दोनों सिरों में बांधने की आवश्यकता है। तत्पश्चात उसे एक कुशल धनुर्धर की भांति बार-बार तीर चलाने का निरंतर अभ्यास करने की आवश्यकता है।

लवली आनंद

आखिर टूटा झूठ का मायाजाल

डा. महेश परिमल

ऊंची सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते, यह पूजा खेडकर के मामले से जाना जा सकता है

आखिर पूजा खेडकर ने जो झूठ का मायाजाल फैलाया था, वह टूट गया। यूपीएससी ने पूजा को हटाते हुए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। अब वह किसी भी परीक्षा में शामिल नहीं हो सकती। इस मामले के उजागर होने से बोगस दिव्यांग सर्टिफिकेट बनाकर नौकरी हासिल करने वालों की नींद हराम हो गई है। झूठ के घोड़ों पर सवार होकर सरपट भागती विवादस्पद प्रशिक्षु आइएएस अधिकारी पूजा खेडकर आखिर जमीन पर आ गई है। फर्जी प्रमाण पत्र के जरिए बिंदास होकर सरकारी नौकरी करने वाली पूजा खेडकर के माता-पिता भी कोई दूध के धुले नहीं हैं। उन पर भी भ्रष्टाचार के आरोप हैं। सोचो, यदि पूजा इसी तरह से आगे बढ़ती जाती, तो आगे चलकर वह कितना भ्रष्टाचार करती? देश की स्सातल में ले जाने में वह बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाती। पूजा तो केवल शुरुआत है, उसके जैसे अभी न जाने कितने ही इस देश को खोखला करने में लगे हुए हैं। आवश्यकता है, ऐसे लोगों की पहचान कर उनके चेहरे को बेनकाब करने की।

वास्तव में देखा जाए तो पूजा की अतिमहत्वाकांक्षा ही उसके लिए गले की हड्डी बनी। इसी महत्वाकांक्षा के चलते उसने अपनी नौकरी के दौरान पहले तो अपने वाहन के लिए विशेष नंबर और लाल बत्ती की मांग की। उसके बाद अपने लिए अलग दफ्तर की फरियाद की। उसकी इस तरह की हरकतों से लोगों का ध्यान उसकी ओर गया। सरकार के नियम-कायदों को जानते हुए भी उसने ऐसी हरकतें कीं, इसलिए उसके झूठ का पर्दाफाश हुआ। स्वयं पर लगे आरोपों को देखते हुए उसने अपने अधिकारियों पर भी झूठे आरोप लगाने शुरू कर दिए। अपने बचाव में उसने अपने आसपास झूठ का एक मायाजाल बना लिया। बाद में वह इसी में उलझती गई। ऊंची सरकारी नौकरी पाने के लिए लोग क्या-क्या नहीं करते, यह पूजा के मामले से जाना जा सकता है। यदि सरकार की ओर से इसे सफाई अभियान माना जाए, तो ऐसे अभियान लगातार चलते रहने चाहिए। अब इसकी भी जांच होनी चाहिए कि क्या यूपीएससी में अंदर से किसी ने पूजा की मदद की है? यूपीएससी को अपनी प्रक्रिया मजबूत करनी चाहिए, ताकि भविष्य में ऐसे मामले दोबारा न हों।

पूजा अकेली नहीं है, हमारे समाज में ऐसे बहुत से लोग हैं, जो आज भी झूठे प्रमाण पत्रों के आधार पर न केवल सरकारी नौकरी प्राप्त कर चुके हैं, बल्कि सेवानिवृत्त भी हो चुके हैं। समाज के ऐसे दुश्मनों को सामने लाने का काम सरकार का है। आम जनता उसका सहयोग कर सकती है, पर सख्त कदम तो सरकार को उठाने होंगे। सरकार का यह सफाई अभियान बदस्तूर चलता रहे, यही कामना की जा सकती है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

जाति की राजनीति पर दोहरा रवैया

'जाति की राजनीति' शीर्षक से प्रकाशित संपादकीय टिप्पणी में इस मुद्दे से जुड़े समग्र पहलुओं पर प्रकाश डाला गया है। बड़े अफसोस की बात है कि आज देश के समग्र राजनीतिक चिंतन और विमर्श में जातिगत मुद्दों की अहम भूमिका हो गई है। इस महामारी की नींव उन्हीं विपक्षी दलों ने रखी है, जिन्होंने संसद में जाति पूंछने पर हंगामा खड़ा कर दिया। इस जातिवाद को समाप्त करने के लिए हमारे तमाम महापुरुषों ने अपना जीवन खपा दिया। इसी दौर के चलते महान एवं गौरवशाली सनातन समाज मध्यकाल में कमजोर हुआ और देश को सैकड़ों वर्षों तक विदेशियों की दासता सहनी पड़ी। हमने अतीत से भी कुछ नहीं सीखा। जो राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना का शोर मचा रहे हैं, जब उनका नाम लिए बिना ही अनुराग ठाकुर ने संसद में जातिगत जनगणना की हिमायत करने वालों की जाति पूछ ली तो इस पर हंगामा खड़ा कर दिया गया। ऐसे में प्रश्न उठता है कि बाहर जाति पूछना बैथ और संसद में अवैध कैसे हो सकता है? जबकि संसद में बैठने वाले ही बाहर निकलते ही जाति-जाति का राग अलापते हैं। हमारे नेता जातिवाद के नाम पर समाज में विष घोलकर सत्ता हथियाने का गंदा खेल खेल रहे हैं। यह खेल देश के विकास में बाधक और राष्ट्र को निर्बल बनाने वाला है।

डा. नरेंद्र टोंक, मेरठ

देश में बढ़ते ट्रेन हादसे

देश में रेल दुर्घटनाएं थमने का नाम ही नहीं ले रही हैं। इस साल पहले छह महीनों में सात बड़ी ट्रेन दुर्घटनाएं हो चुकी हैं और 2023 में बालासोर हादसे में 290 लोग मारे गए थे। ट्रेन हादसों की सिर्फ मौत के आंकड़ों से नहीं देखा जा सकता। ऐसे हादसे यात्रियों के लिए कहर बनकर टूटते हैं। इन सबकी भरपाई मुआवजे से नहीं हो सकती। दुर्घटनाएं तो पहले भी होती थीं। सच ये है कि पहले की तुलना में कम हो रही हैं। 2014 से 2023 के बीच सालाना औसतन 72 ट्रेन हादसे हुए, जबकि 2004 से 2014 तक सालाना औसतन 171 ट्रेन हादसे होते थे। बढ़ते ट्रेन हादसों का एक कारण ट्रेनों की बढ़ती रफ्तार को भी बताया जा रहा है। ट्रेनों की बढ़ती स्पीड को प्रगति का पैरामीटर मान लिया गया है। जबकि गति के अनुरूप पटरियां, सिग्नल सिस्टम आदि को तैयार नहीं किया गया। लोको स्टाफ सहित अन्य कर्मचारियों पर भी काम का बोझ बढ़ा है। रेलवे में फिलहाल डेढ़ लाख पद खाली पड़े हैं। पटरियों की जर्जर हालत भी बढ़ती दुर्घटनाओं का मुख्य कारण है। ट्रेन दुर्घटनाओं की जांच के मामलों में भी पारदर्शिता की जगह लीपापोती ज्यादा दिखती है। रेल दुर्घटनाओं को रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा पर गठित खन्ना कमेटी भी ठंडे बस्ते में पड़ी है। ट्रेन हादसों को रोकने के लिए सरकार ने वर्ष 2020 में टक्कर विरोधी व्यवस्था कवच की शुरुआत की थी, जो अभी तक कुल रेल रूट के दो प्रतिशत से आगे नहीं पढ़ पाई है। ऐसे में सरकार की पहली प्राथमिकता दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाना होना चाहिए जिससे जान माल की रक्षा हो सके।

चंद्र प्रकाश शर्मा, दिल्ली

मेलबाक्स

जाति पूछने पर हंगामा क्यों?

जाति विवाद को तूल देने वाली कांग्रेस पार्टी के नेता की जाति पूछी गई तो कांग्रेस ने सदन में नरेंबाजी की। राहुल अक्सर जाति पूछते नजर आते हैं। जब सदन में जाति विवाद ने तूल पकड़ा तो कांग्रेस ने अपना आपा खो दिया। हिंदू और हिंदुत्व की व्याख्या करने वाले राहुल की जब अनुराग ठाकुर ने अनावस हो जाति पूछी तो कांग्रेस हवाहवाई हो गई। इस पर कांग्रेसी नेता रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने कहा है कि दुनिया की जाति बताने वाले राहुल अपनी जाति भी बताएं। कांग्रेस आरएसएस, भाजपा और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को गालियां देकर वोट बैंक खड़ी करने निकलती है। कांग्रेसी की नजर में हिंदुओं को गाली देन पंथनिरपेक्षता है। कांग्रेस विपक्ष में बैठकर बेतुके बयान देकर सदन की कार्यवाही स्थगित कराने और सदन का समय खराब करने के स्थान पर देश के विकास के कार्यों को प्राथमिकता दे जिससे सदन का कीमती समय बच सकता है।

कांतिलाल मांडोत, दिल्ली

इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त करने के लिए घटनाक्रम सादर आमंत्रित है। आप हमें पत्र भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं।
अपने पत्र इस पते पर भेजें:
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण,
डी-210-211, सेक्टर-63, नोएडा
ई-मेल: mailbox@jagran.com

संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त, पूर्व प्रधान संपादक-स्व.नरेन्द्र मोहन, नॉन एग्जीक्यूटिव चेयरमैन-महेन्द्र मोहन गुप्त, प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 501, आई.एन.एस. बिल्डिंग, रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-210, 211, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक (राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी*
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 011-43166300, नोएडा कार्यालय : 0120-4615800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.I. No. DELHIN/2017/74721 *इस अंक के प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई/रेल शुल्क ₹-2 अतिरिक्त।

****

संवाद

नवभारत टाइम्स

नवभारत टाइम्स । नई दिल्ली। शनिवार, 3 अगस्त 2024

वायनाड के सबक़

कुदरत के संदेश की अनदेखी अब और नहीं

अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए मशहूर केरल के वायनाड में इन दिनों तबाही और खौफ का मंजर पसरा हुआ है। यह नतीजा है पर्यावरण से खिलवाड़, हमारे अंतहीन लालच और चेतावनियों की अनदेखी का। लैंडस्लाइड में मरने वालों की संख्या 300 को पार कर गई है। राज्य सरकार कह रही है कि बचाव कार्य चंद दिनों में पूरा होने वाला नहीं। लेकिन, क्या इस सवाल का जवाब सरकार या किसी के भी पास है कि वायनाड में हमने जिन्हें खोया और जो गंवाया, उसकी जिम्मेदारी किस पर है?

लैंडस्लाइड में 300 से अधिक मरे

हादसे की वजह | ISRO के हैदराबाद सेंटर ने प्रभावित इलाके की सैटलाइट तस्वीरें ली हैं। उसके मुताबिक 1,550 मीटर की ऊंचाई पर भारी बारिश के चलते भूस्खलन हुआ। पानी के साथ बड़े पैमाने पर मलबा आया, तो भूस्खलन का दायरा बढ़ता गया। यह तो वह वजह है, जो चंद तस्वीरों से नजर आती है और तात्कालिक है। सारा दोष भारी बारिश पर मढ़ देने से काम नहीं चलेगा।

खतरे वाली जगह | केवल केरल ही नहीं, पूरा पश्चिमी घाट पर्यावरण की दृष्टि से बेहद संवेदनशील है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने 2022 में संसद में बताया था कि 2015 से 2022 के दरम्यान देशभर में 3,782 भूस्खलन दर्ज किए गए थे। इनमें से 59% से ज्यादा घटनाएं सिर्फ केरल में हुईं। देश के जिन 30 जिलों में लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा है, उनमें से 10 तो सिर्फ केरल में हैं।

घटती हरियाली | वायनाड यूं ही अचानक लैंडस्लाइड प्रोन एरिया नहीं बन गया। 2022 की एक स्टडी बताती है कि 1950 से 2018 के दौरान वायनाड में जंगल का एरिया 62% तक घट चुका है। हालांकि सरकार पौधारोपण करती है, लेकिन क्या रोपे गए पौधे सदियों से आबाद जंगलों की जगह ले सकते हैं?

फाइलों में बंद सुझाव | भारत सरकार ने साल 2011 में वेस्टर्न घाट इकॉलजी एक्सपर्ट पैनल गठित किया था। इस पैनल ने पश्चिमी घाट को इको-सेंसिटिव घोषित करने की सिफारिश की थी। साथ ही सुझाव दिया था कि पारिस्थितिक संवेदनशीलता के आधार पर इस इलाके को जोन में बांटा जाए और उसके हिसाब से इंसानी गतिविधियों पर लगाम लगाई जाए। ये सिफारिशें फाइलों में ही पड़ी रहीं। क्षेत्र में बेहिसाब निर्माण होते रहे, खनन गतिविधियां चालू रहीं, जंगलों को काटा जाता रहा।

कठिन काम का समय | वायनाड जैसी आपदाएं आती रहती हैं, लेकिन हम सबक सीखने को तैयार नहीं। सच है कि विकास का पैटर्न, आर्थिक गतिविधियों की दिशा बदलना आसान नहीं, लेकिन यह कठिन काम अब और टाला नहीं जा सकता। ये आपदाएं प्रकृति की ओर से भेजी जाने वाली गंभीर चेतावनी हैं, जिनकी अनदेखी सबके लिए घातक होगी।

दो दूनी चार

रिस्क से इश्क

रमेश तिवारी

बाजार में निवेश जोखिमों के अधीन है, ये बात हम अरसे से सुनते आ रहे हैं। इसके बावजूद 'हैरतअंगेज रिटर्न' पाने का चस्का होता है। इसी चाह में जुआ बरसों से खेला जाता है। सट्टे का बाजार भी कम नहीं। अब एक नई चिंता सामने आ गई है। शेयरों के डेरिवेटिव्स की ट्रेडिंग, जो बाजार में इन दिनों फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के नाम से चर्चित है। इसमें रिटेल निवेशकों की दनादन बढ़ोतरी से इकॉनमी को नुकसान हो रहा है। मार्केट रेगुलेटर सेबी और सरकार के लोग लगातार इस बारे में चेता रहे हैं। सेबी ने हाल में कहा कि वो कड़े कदम उठाने के लिए तैयार है। माना जा रहा है कि कदम उठे तो सौदों का वॉल्यूम 30 से 40 पर्सेंट कम हो सकता है।

वैसे तो कहा जा सकता है कि अगर आम आदमी खुद से अपना पैसा रिस्की असेट्स में लगा रहा है तो सरकार उसे क्यों रोके। लेकिन डेटा बता रहा है कि इस चिंता की ठोस वजहें हैं। पहले ये समझ लें कि डेरिवेटिव सौदे किए ही क्यों जाते हैं। इसे यूं समझ लें कि कोई शिकंजी की दुकान चलाता है। आज वो 5 रुपये में एक नींबू खरीदता है। एक महीने बाद नींबू का दाम 7 रुपये हो जाए तो उसे दिक्कत हो सकती है। वो नींबू बेचने वाले से पहले ही सौदा कर लेता है। सौदा ये कि एक महीने बाद दाम चाहे दाम 3 रुपये हो जाएं या 8 रुपये, वो एक नींबू के 5 रुपये ही देगा। इस तरह शिकंजी वाला नींबू के दाम बढ़ने का रिस्क कम कर लेता है। कीमत में बढ़ोतरी के रिस्क से बचने के लिए दुनिया भर में निवेशको को डेरिवेटिव्स सौदों की इजाजत दी गई।

भारत में 2020 के बाद डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग सुपरहिट हो गए। निवेशकों की जो फौज आई, उसमें बड़ी संख्या उन लोगों की थी जिन्होंने न तो म्युचुअल फंड को चुना, न ही डायरेक्ट शेयरों में निवेश को। वो डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के दीवाने हो गए। पिछले करीब चार साल में डेरिवेटिव ट्रेडिंग में रिटेल निवेश का टर्नओवर डबल हो गया। लेकिन सेबी चीफ ने हाल में कहा कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस ट्रेडिंग में भारत में लोग हर साल 60 हजार करोड़ रुपये तक गंवा रहे हैं। समझा जा रहा है कि इस नुकसान में घरेलू बचत का बड़ा हिस्सा डूब गया, जिसे किसी दूसरे उपयोगी असेट्स में लगाया जा सकता था। सेबी की पुरानी स्टडी बताती है कि इसमें 90 पर्सेंट ट्रेडिंग में नुकसान होता है।

मार्केट में स्थिरता बनी रहे, निवेशकों के हितों को नुकसान न हो, ये सेबी की जिम्मेदारी है। ब्रोकरों और स्टॉक एक्सचेंजों को भले ही नुकसान हो, लेकिन सेबी का प्लान ये है कि इन सौदों से जुड़ने के लिए कम पैसे वाले लोगों को हतोत्साहित किया जाए। सरकार ने भी बजट प्रस्ताव में फ्यूचर और ऑप्शन सेगमेंट पर सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स बढ़ाने की बात कही है। आर्थिक सर्वे में कहा गया था कि एक विकासशील देश में रिटेल इन्वेस्टर अटकलबाजियों में दिलचस्पी ले, ये ठीक नहीं है। आगे ये भी देखना होगा कि अटकलबाजियों की हरकत शेयर बाजार के दूसरे सेगमेंट में न शुरू हो जाए, जैसे स्मॉल कैप शेयर। या फिर कोई समानांतर व्यवस्था न खड़ी हो जाए, जिस पर सेबी की नजर न हो। इसी वजह से एक नया असेट क्लास लाने की तैयारी चल रही है, जहां रिटेल ट्रेडर्स की रिस्क लेने की भूख मिटाई जा सके।

ऑफ दि ट्रैक

ईको फ्रेंडली बैक्टीरिया

दिलीप लाल

नॉन-स्टिक बर्तन, कुकवेयर, वाटरप्रूफ कपड़े, फूड पैकेजिंग और फायर फाइटिंग फोम बनाने में जिन केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, वे per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) समूह के होते हैं। इस तरह के केमिकल्स पानी, धूल और तेल के प्रतिरोधक होते हैं, इसलिए इन उत्पादों में इनका इस्तेमाल होता है। ये आसानी से नष्ट नहीं होते और पर्यावरण में लंबे समय तक टिके रहते हैं, इसलिए इन्हें 'forever chemicals' भी कहते हैं। ये स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। अध्ययन बताते हैं कि इनसे कैंसर, थायराइड, हाई कोलेस्ट्रॉल और इम्यून सिस्टम से जुड़ी समस्याएं भी पैदा हो सकती हैं। लिहाजा PFAS समूह के केमिकल्स ने दुनिया की चिंता बढ़ा दी है और इनके प्रभाव को खत्म करने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम चल रहा है। इसी क्रम में यूनिवर्सिटी ऑफ नेब्रास्का-लिंकन में हुए एक शोध में वैज्ञानिकों ने गंदे पानी में मौजूद ऐसे बैक्टीरिया की खोज कर ली है, जो खास तरह के 'फॉरेवर केमिकल्स' को नष्ट कर देते हैं। हालांकि PFAS के उपचार के लिए पहले से ही कुछ प्रभावी तरीके मौजूद हैं, जैसे कि फिल्ट्रेशन और हीट ट्रीटमेंट। लेकिन, बैक्टीरिया से इन रसायनों के प्रभाव को कम करने का तरीका बेहतर और आसान हो सकता है, क्योंकि इस काम में लागत कम आएगी। साथ ही प्रदूषित हो रहे ग्राउंडवाटर को भी ठीक करने के लिए आसानी से इस बैक्टीरिया को इंजेक्ट किया जा सकेगा।

सत्य घटनाओं पर आधारित 'गोट लाइफ' में दर्ज हुआ प्रवासियों का दर्द

मलयालम सिनेमा क्यों है ख़ास

दुष्यन्त

हाल के सालों में तेलुगु, तमिल और कन्नड़ फिल्मों का उत्तर भारत में एक अलग, उत्सवपरक स्वागत हमने देखा है। इस सिलसिले में मलयालम ने अलग ही तेवर, मिजाज और स्वाद के साथ खुद को दाखिल किया है। यह दखल बड़ा मानीखेज है। पोस्ट कोविड एक भ्रम यह भी फैला कि हिंदी के समक्ष दक्षिण की चुनौती है। दरअसल यह एक तथ्यहीन सरलीकरण था, क्योंकि दक्षिण का सिनेमा 4 भाषाओं का सिनेमा है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ के बाद, जिसका चौथा रंग अब खिलने लगा है। यह है मलयालम का सिनेमा।

बदलाव की आहट | यूं कुल मिलाकर बुनियादी बात हो सकती है कि सुदूर दक्षिण की कहानियां धुर उत्तर तक असर कर रही हैं, अपनी बहुआयामी अलग खुशबू से हम सबको महका रही हैं। यह मुझे ऐतिहासिक भारतीयता की अंतर्निहित गर्भनाल संबद्धता का भी पुनर्जागरण लगता है। उत्तर भारतीय दर्शक पहले दक्षिण की डब फिल्में देखते थे, या कभी-कभार रीमेक। अब ओटीटी पर सबटाइटल्स के साथ ओरिजिनल मलयालम देखने की प्रवृत्ति हिंदी पट्टी में बढ़ी है। यह खास प्रवृत्ति है जिसे रेखांकित करने की जरूरत है। इससे भारतीय भाषाओं के सिनेमा और पैन इंडियन सिनेमा के आने वाले सालों में और बदलने की आहट महसूस की जा सकती है। भौगोलिक अर्थों में, यह केवल बाहरी बदलाव नहीं है, केरल के भीतर भी यह गौरव बोध भी विकसित हुआ है कि उनके सिनेमा की भारत से बाहर तारीफ होने लगी है। यह अभिनेताओं और मेकर्स दोनों में आ रहा है।

जड़ों पर केंद्रित दृष्टि | यह बड़ा अंतर है, इसे एक दार्शनिक, दूरदर्शी और जड़ों पर केंद्रित होने की दृष्टि को चुनने की तरह देखना चाहिए। कमाल यह है कि इसका अच्छा नतीजा बॉक्स ऑफिस पर भी दिख रहा है। उन कहानियों की खूबी यह भी है कि वे कहानियों से पैदा हुई कहानियां नहीं हैं, यानी उनके रेफरेंस साहित्य या सिनेमा से नहीं उठाए गए हैं। वे कहानियां सीधे जीवन या ज़मीन से उठाई गई हैं। हिंदी सिनेमा के दर्शक के रसास्वादन का स्टीरियो टाइप टूटने की तरह भी इसे देखना चाहिए।

मलयालम सिनेमा की खूबी

- जीवन के छोटे-छोटे मसलों पर केंद्रित कहानियां
- नजर आती है अपनी जड़ों पर केंद्रित दृष्टि
- इन फिल्मों में डिवेलप हो रही संगीत की नई धारा

थाली में नई डिश | एक दूसरा स्टीरियो टाइप और भी टूटता दिख रहा है कि पिछले कुछ सालों में जो दक्षिण के अतिनाटकीय सिनेमा ने उत्तर के दर्शकों को मोहित किया, वह रसास्वादन भी शायद कमज़ोर पड़ने लगा है। ऐसे में मलयालम का सिनेमा उनकी थाली में नई डिश की तरह आया है। क्या पता हिंदी दर्शक के चटोरेपन के ये ट्रेड्स स्थायी न बन पाएं और वे हिंदी सिनेमा की पुरानी दाल रोटी पर लौट आएं कि वही स्थायी भाव है। इसका ठीक ठीक जवाब अभी किसी के पास नहीं होगा। प्रवासियों का संघर्ष : कमोबेश हाल का सारा मलयालम सिनेमा कहानी केंद्रित सिनेमा है। इस साल आई चर्चित मलयालम फिल्मों में 'गोट लाइफ' नाम की एक काफी बड़ी सुंदर फ़िल्म है। बड़ी मुश्किलों से बनी है, दुबई में रिलीज पर प्रतिबंध भी लगे हैं। अरब जाने वाले प्रवासियों की कहानी है, जो सत्य घटनाओं पर आधारित है। उनके संघर्ष और सर्वाइवल की कहानी है। 'द ग्रेट इंडियन किचन' को ही यह कीजिए, कैसे हमारे जेंडर स्टीरियो टाइप को झकझोरती हुई फिल्म थी।

गूगे का गुड़ | 'अन्वेशिपिन कंडेथुम' के बिना तो इस साल के मलयालम सिनेमा की बात ही नहीं पूरी हो सकती। इसने भी बॉक्स ऑफिस पर कमाल किया, 8 करोड़ में बनी फिल्म 40 करोड़ कमा गई। कई स्तरों की कहानी, उपकथाओं में अलग जादू है और क्लाइमेक्स और कथार्सिस के तो क्या ही कहने! बस ये समझिए कि यह फिल्म गूगे का गुड़ है। ऐसी ही फिल्म है 'आवेशम'। फहाद फासिल की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर मलयालम सिनेमा के तो रेकॉर्ड तोड़े ही, इस साल भारत की सभी भाषाओं की सबसे कमाऊ फिल्मों में अपना नाम दर्ज किया। फिल्म के गीतकार विनायक शशिकुमार को याद न करना तो गुनाह ही होगा।

संगीत की बदली धारा | एक और पहलू है जो मलयालम फिल्मों को हिंदी दर्शकों के मन के करीब लाता है, वह है संगीत। सुशिन श्याम, सूरज एस कुरूप, शान रहमान और जस्टिन वर्गीस जैसे संगीतकारों ने मलयालम फिल्मों के संगीत की धारा ही बदल दी है। इतना ही नहीं, वहां पर अनु एलिजाबेथ ऐसी गीतकार हैं जिन्होंने मलयालम फिल्मी गीतों को मेल गेज से बाहर लाने का काम किया है, लगभग वही काम हिंदी सिनेमा में कौसर मुनीर कर रही हैं। इन गीतकारों- संगीतकारों के संगीतमय कांधों पर टिकी ये फिल्में या तो न्यूनतम संगीत वाली गीत रहित फिल्में हैं या फिर लोक के जादू से सजी, परंपरागत भारतीय गीत परंपरा के अनुरूप गीतों वाली फिल्में।

छोटे मसले, बड़ी कहानी | हालिया मलयालम सिनेमा अपने अलग से, अछूते विषयों के कारण तुरंत दर्शक को मोहता है। छोटे-छोटे विषयों उनको उठाकर कहानी बुनी जा रही है, जैसे बाढ़ पर, गांव के छोटे-छोटे मसलों पर कहानियां बन रही हैं। शहरी जीवन पर कम मलयालम सिनेमा दिखता है। हिंदी सिनेमा का शहरीकरण तो कई दशकों में हुआ ही है, अब तो महानगरीकरण की तरफ बढ़ चुका है। इसके बरक्स मलयालम सिनेमा अपने जमीनी दर्शकों के लिए फिल्में बना रहा है।

गुलदस्ते में नए फूल का महकना | हिंदी में वह जगह इंडी म्यूजिक या आजाद संगीत भर रहा है। और हिंदी इंडी म्यूजिक देखते ही देखते हिंदी फिल्मी गीतों से बड़ा हो गया है, अपने प्रभाव में भी, अपने बाजारी आकार में भी। मलयालम सहित हिंदी से इतर भारतीय भाषाओं में से किसी भी भाषा के सिनेमा का बड़ा होना कुल मिलाकर सच्चे अर्थों में भारतीय सिनेमा का बड़ा होना है, उस गुलदस्ते में नए फूल का खिलकर महकना है।

(लेखक फ़िल्म राइटर और गीतकार हैं)

चुनाव का बदला सीन

अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की उम्मीदवार कमला हैरिस की अप्रूवल रेटिंग बढ़ रही है। कुछ सर्वे में उन्होंने प्रतिद्वंद्वी डॉनल्ड ट्रंप को पीछे छोड़ दिया है। ऐसे में जानते हैं उनके पक्ष-विपक्ष की बातें :

AI image

पड़ोस में रोजगार

कमला हैरिस ने कई बड़ी कंपनियों को ग्वाटेमाला, हौंडुरास और अल सल्वाडोर में निवेश के लिए राजी किया। सोच थी कि इन देशों में रोजगार बढ़ा तो यहां से अमेरिका में होने वाला माइग्रेशन रुक जाएगा। उनके प्रयासों से 30 हजार नौकरियां पैदा हुईं, 60 हजार लगभग पाइपलाइन में हैं।

रिफ्यूजी प्रोग्राम चलाए

हैरिस ने सेंट्रल अमेरिका की सरकारों के साथ मिलकर रिफ्यूजी प्रोग्राम के लिए काम किया। लेकिन आलोचक कहते हैं कि मैक्सिको बॉर्डर पर ध्यान नहीं दिया गया, जहां से सबसे ज्यादा माइग्रेशन होता है।

5 पॉइंट

विरासत का साथ

कमला हैरिस की मां भारतीय मूल की हैं, जबकि पिता जमैका के। परिवार से मिली विविधता की यह विरासत उनके पक्ष में जाती है। अमेरिकी चुनाव में अश्वेत, दक्षिण एशियाई मूल के लोगों की बड़ी भूमिका होती है। भारतीयों का दबदबा काफी बढ़ा है। हालांकि इसी वजह से हैरिस को डॉनल्ड ट्रंप की आलोचना का शिकार भी बनना पड़ रहा है।

बंदूक के खिलाफ

हैरिस US गन कल्चर पर लगाम के पक्ष में हैं। 2019 में इस बारे में एक बिल लाने की तैयारी थी, जिसे सपोर्ट किया था। इसी वजह से US के नैशनल राइफल असोसिएशन की पॉलिटिकल विंग ने उन्हें 'F' रेटिंग दी यानी विरोधी माना है। US चुनावों में गन लॉबी हावी रहती है, उसका विरोध भारी पड़ सकता है।

स्विंग वोटर्स की चुनौती

कमला हैरिस एक सफल प्रोसिक्यूटर रही हैं, लेकिन माना जाता है कि एक राजनेता के तौर पर वह अपना विजन नहीं रख पातीं। वह कैलिफोर्निया से आती हैं, जहां डेमोक्रेट्स का गढ़ है पर राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें स्विंग वोटर्स को अपने पाले में लाना होगा।

प्रस्तुति : शैलेश पांडेय

बिना खर्च 71 हज़ार सीटें बढ़ जाएंगी

फ्लैगशिप अदिति स्कीम के साथ Narayana Health (NH) देश की ऐसी पहली हॉस्पिटल चेन बन गई है, जिसने हेल्थ इंश्योरेंस विजनरेस में कदम रखा है। हॉस्पिटल चेन के संस्थापक चेयरमैन डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी ने ***केआर बालसुब्रमण्यम*** *के साथ बातचीत में इंश्योरेंस और हेल्थकेयर सेक्टर के बारे में अपनी राय रखी। पेश हैं इस इंटरव्यू के खास अंश:*

सप्ताह का इंटरव्यू

डॉ. देवी प्रसाद शेट्टी

■ आज भी देश में हेल्थकेयर इंश्योरेंस के दायरे में आने वाले लोगों की संख्या इतनी कम क्यों है?

भारत में हितों के टकराव की वजह से हेल्थ इंश्योरेंस बहुत लोकप्रिय नहीं है। यहां अस्पतालों, मरीजों और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच आपसी भरोसा नहीं है। इंश्योरेंस डेटा से पता चलता है कि जिन लोगों ने मेडिकल बीमा कराया है, उनमें से 5% से कम ही डायबिटीज के मरीज हैं। इस आंकड़े पर भरोसा करना मुश्किल है। दरअसल, बीमारियों के बारे में इंश्योरेंस कंपनियां बीमा करवाने वाले की बात पर भरोसा करती हैं। वे प्रीवेटिव हेल्थ चेकअप पर जोर नहीं देतीं और अक्सर बीमा कंपनियां मरीज के अस्पताल में भर्ती होने के बाद उसका क्लेम खारिज कर देती हैं। फर्ज कीजिए कि मैं एक अस्पताल चला रहा हूं और एक इंश्योरेंस कंपनी भी। यहां हितों का टकराव नहीं है क्योंकि भुगतान एक ही कंपनी की ओर से होना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सिर्फ अस्पताल चला रहा है तो उसके लिए यही अच्छा होगा कि अधिक से अधिक लोग वहां इलाज करवाने आएं। अब मान लीजिए कि मैं इंश्योरेंस कंपनी भी चला रहा हूं तो मैं यही चाहूंगा कि लोग बीमार न पड़ें। वैसे यह बात भी सही है कि आग लगने की घटना या किसी हादसे के बारे में अंदाजा नहीं लगाया जा सकता, लेकिन हार्ट अटैक के बारे में 90% तक सही अंदाजा लगाया जा सकता है।

■ आप अदिति स्कीम का पायलट प्रॉजेक्ट चला रहे हैं, यह कैसा चल रहा है?

हम अपनी लागत पर हेल्थ चेकअप करेंगे। मेरा मानना है कि किसी भी व्यक्ति के स्वास्थ्य को 24x7 मॉनिटर करना संभव है और हमारी इंश्योरेंस कंपनी ऐसा करेगी। अगर किसी को डायबिटीज है तो हम इस रोग को नियंत्रित करने की कोशिश करेंगे। अगर किसी व्यक्ति ने हमारी कंपनी से बीमा करवाया है और अचानक उसकी सेहत खराब हो जाती है तो वह हमारे ऐप पर टैप करके अपनी परेशानी बता सकता है। हमारे डॉक्टर उस मरीज का डेटा देखकर जरूरत पड़ने पर दवा सुझाएंगे। हमने मैसूरू में स्कीम लॉन्च की है और जल्द ही इसका विस्तार बेंगलुरु, दिल्ली और कोलकाता में करेंगे। हमारी इंश्योरेंस स्कीम में उम्र और हेल्थ प्रोफाइल के हिसाब से प्रीमियम तय होगा।

■ इस में आप कितना पैसा निवेश करने जा रहे हैं?

हमने इसमें 100 करोड़ रुपये लगा दिए हैं और आगे लगाने के लिए 100 करोड़ रुपये रखे हैं। पैसा हमारे लिए कोई मसला नहीं है। हालांकि, हम इंश्योरेंस स्कीम शुरू कर पाए, इसके लिए मैं बीमा नियामक IRDA का शुक्रगुजार हूं। मुझे तो पहले लगा था कि इंश्योरेंस के लिए हमें कभी लाइसेंस नहीं मिलेगा। इसी वजह से हमने कुछ इंश्योरेंस स्टार्टअप्स में निवेश शुरू कर दिया था।

■ ऐसा लग रहा है कि आपकी इंश्योरेंस स्कीम से इस सेक्टर में उथलपुथल मचेगी...

देखिए, हर कंपनी का अपना एक रास्ता होता है। मुझे लगता है कि आगे चलकर हर किसी के पास किसी न किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस होगा। हम इस कारोबार में ऐसी चीज पर फोकस कर रहे हैं, जो हमारे दिल के बेहद करीब है। इसके साथ हम पहले हॉस्पिटल ग्रुप हैं, जिसने इंश्योरेंस कारोबार में कदम रखा है।

■ सरकार इस मामले में किस तरह से मदद कर सकती है?

सरकार को टैक्स फ्री हेल्थ सेविंग्स एकाउंट जैसे ऑप्शन लाने पर विचार करना चाहिए। अमेरिका और सिंगापुर में यह काफी लोकप्रिय है। मैं देश में अमीर परिवारों से यह भी कह रहा हूं कि वे अपने एंप्लॉयीज के इंश्योरेंस प्रीमियम का एक हिस्सा चुकाकर उन लोगों को तोहफा दें। कोई भी सरकार नागरिकों के हेल्थकेयर की पूरी लागत नहीं उठा सकती। समय के साथ लोगों की औसत उम्र बढ़ेगी। इसलिए हमें कम खर्च में मेडिकल इंश्योरेंस को लोकप्रिय बनाना होगा।

■ सरकार के पूरे खर्च से चलने वाले हेल्थकेयर के बारे में आपकी क्या राय है?

> अस्पतालों, मरीजों और इंश्योरेंस कंपनियों के बीच आपसी भरोसा नहीं है। अक्सर बीमा कंपनियां मरीज का क्लेम खारिज कर देती हैं। फर्ज कीजिए कि मैं एक अस्पताल चला रहा हूं और एक इंश्योरेंस कंपनी भी। यहां हितों का टकराव नहीं है क्योंकि भुगतान एक ही कंपनी की ओर से होना होता है

जिन देशों की आबादी कम है, वहां ऐसी व्यवस्था अच्छी रहती है। लेकिन अगर किसी देश की आबादी 1.5 करोड़ से अधिक हो तो यह व्यवस्था चरमराने लगती है।

■ NDA सरकार का तीसरा कार्यकाल शुरू हो चुका है। आप सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे?

देश में मेडिकल की सीटें बढ़नी चाहिए। कई साल पहले की बात है, तब इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेजों में दाखिला आसान नहीं होता था। लेकिन आज सीटों की संख्या बढ़ने से इंजीनियरिंग कॉलेजों में ऐसी स्थिति नहीं रह गई है। यहां कोई स्कैंडल नहीं होते। लेकिन मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए 20 एकड़ जमीन और 600 करोड़ रुपये के निवेश की जरूरत पड़ती है। यह सफेद हाथी पालने जैसा है। कैरिबियाई देशों में, जो अमेरिका के लिए डॉक्टर तैयार करता है, वहां आप 14 करोड़ रुपये में एक मेडिकल कॉलेज खरीद सकते हैं। भारत में जब तक मेडिकल कॉलेजों को लेकर यह स्थिति नहीं बदलेगी, तब तक गरीब परिवारों के बच्चे डॉक्टर नहीं बन पाएंगे, जबकि दुनिया में शानदार डॉक्टर गरीब परिवारों से आते रहे हैं।

■ सरकार इस स्थिति को कैसे बदल सकती है?

पिछले 8 वर्षों में MBBS सीटों की संख्या दोगुनी हुई है। PG सीटें भी डबल हो गई हैं। भारत में जब हम डॉक्टरों, नर्सों और टेकनीशियंस के बारे में प्लानिंग करते हैं तो हमें दुनिया की जरूरतों को देखकर यह काम करना होगा। दुनिया में 8 करोड़ हेल्थकेयर वर्कर्स की कमी है। कोई एक देश इस कमी को पूरा नहीं कर सकता। देश में हजारों सुपर स्पेशिएलिटी हॉस्पिटल हैं, जो नैशनल बोर्ड ऑफ एक्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBE) के तहत PG ट्रेनिंग कराते हैं। हमें हर साल 100 स्टूडेंट्स दीजिए। इनके अलावा, देश में 710 मेडिकल कॉलेज हैं। इनमें से हरेक में 100 सीटों की अलग से व्यवस्था की जाए और उन्हें जिला और तालुका लेवल के अस्पतालों से जोड़ा जाए। इस तरह से बिना किसी लागत के 71 हजार मेडिकल सीटें बढ़ जाएंगी।

www.nbt.in

तो गोली मार दूंगा आपको!

मध्य विद्यालय सरायरंजन में लर्निंग फेस्टिवल का आयोजन हो रहा था। प्रारूप के अनुसार छह दिनों तक चलने वाले इस फेस्टिवल में स्कूल के सभी बच्चों को उनकी इच्छा के अनुसार स्टूडियो में नामांकित किया जाता है। स्टूडियो की गतिविधि के अनुसार बच्चे क्रियाकलाप कर अपनी क्षमता प्रदर्शित करते हैं। अचानक मेरी निगाह विज्ञान स्टूडियो में बैठे दिलीप पर गई। उसे देखते ही मेरे पैर एकाएक रुक गए। मैंने जिज्ञासावश पूछा, 'दिलीप तुम क्या बना रहे हो?' उसने पूरे उत्साह के साथ कहा - सर, मैं सोलर सिस्टम पावर प्रॉजेक्ट बना रहा हूं। मैं थोड़ी देर वहीं रुक कर उसके प्रयासों को गौर से देखता रहा। वहां से निकलने पर मेरे दिमाग में पुरानी यादें दौड़ने लगीं।

आज से एक साल पहले यह हाल था कि दिलीप विद्यालय बिलकुल नहीं आना चाहता था। कभी आ भी गया तो इंटरवल में ही भागकर घर चला जाता। समुदाय भ्रमण के दौरान जब मैं उसके अभिभावक से मिलता तब वे भी दिलीप की आदत से बहुत परेशान दिखते। एक दिन तो वह मुझे ही धमकी देते हुए कहने लगा, 'यदि आप मेरे पिताजी या घर के किसी भी सदस्य से मिलिएगा और मेरे बारे में बात कीजिएगा तो मैं आपको गोली मर दूंगा।' लेकिन मुझे उस बच्चे में संभावनाएं दिख रही थीं। मैंने उसे छूट दी कि तुम विद्यालय आ कर जो भी विषय पढ़ना चाहो, वही पढ़ो। साथ ही मैंने विज्ञान की किताब खोलकर दिखाते हुए कहा, 'इसमें बहुत सारी एक्टिविटीज हैं, चाहो तो इनमें से कोई भी कर सकते हो।' इसका उस पर आश्चर्यजनक असर हुआ। वह विद्यालय आने लगा। मैंने कुछ और प्रयोग किए। होमवर्क में मैं उससे सोशल साइंस से जुड़े अपने अनुभव लिखकर लाने को कहने लगा। मैंने देखा कि विद्यालय और पढ़ाई में उसकी अरुचि कम होने लगी। अब वह जातिगत भेदभाव, दहेज प्रथा, चुनाव प्रक्रिया, पुलिस के कर्तव्य और लोगों के नागरिक अधिकार जैसे विषयों पर रोज लिखकर लाता और सभी बच्चों को सुनाता। प्रस्तुति के दौरान कक्षा के बच्चे जब उसकी बात पर ताली बजाते तो उसे बहुत अच्छा लगता।

खुद अपनी आंख से

अभिषेक कुमार

एक दिन वह मेरे पास आया और बोला कि मेरे पिताजी ने आज शाम आपको घर बुलाया है। शाम को उसके घर पहुंचा तो दिलीप के पिताजी ने मुस्कुराते हुए मेरा स्वागत किया और बोले, 'आज आप रात का खाना मेरे साथ ही खाएंगे।' मैंने जिज्ञासावश पूछा आज कुछ खास है क्या? इतने में दिलीप की मां बोल पड़ीं, 'कुछ खास नहीं है, लेकिन हमारी इच्छा है कि आज आप हमारे घर भोजन करें।' खाने के बाद अकेले में दिलीप के पिता बोले, 'मैंने आज आपको भोजन पर इसलिए बुलाया क्योंकि मेरा बच्चा देखे कि जब मेरे पिताजी शिक्षक की इतनी इज्जत करते हैं तो मुझे भी इनकी इज्जत करनी चाहिए। यह जानकर मैं चिंतित था कि उसने आपको गोली मारने की बात कह दी थी। लेकिन उसके स्वभाव और व्यवहार में बहुत बदलाव आया है। और यह आपकी ही कोशिशों से हुआ है।' उस दिन दिलीप के पिता का परिपक्व अंदाज मुझे हतप्रभ कर गया था पर आज लर्निंग फेस्टिवल के विज्ञान स्टूडियो में दिलीप को काम करता देख मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैंने सचमुच वर्ल्डकप जीत लिया हो।

चलते-चलते...

मच्छरों का मौसम फिर आने वाला है और उनके साथ आएंगी डेंगू, चिकनगुनिया जैसी बीमारियां। पिछले 50 बरसों में इन रोगों का खतरा बेहद बढ़ गया है। अब एक अच्छी खबर आई है इंडोनेशिया से, जहां ड्रोन की मदद से सर्वे कर मच्छरों का लार्वा नष्ट किया गया। इस उपाय से डेंगू में 77% की कमी आई है। अपने देश में यह तरीका अपनाया जा सकता है।

रीडर्स मेल

▶ स्थायी समाधान मिले

यह पत्र 2 अगस्त के लेख 'रेलवे का खर्च बढ़ा पर सेवाएं हुईं खराब' पढ़ा। लेखक ने आज के हालात को एकदम सटीक अंदाज में बयां किया है। रेलवे के आधुनिकीकरण पर अरबों-खरबों रुपये खर्च किए जा चुके हैं। हर नई सुविधा के लिए योजनाएं बनती रहती हैं। बड़े खर्च ने रेलवे की यात्रा को आरामदेह तो बना दिया, लेकिन बढ़ती दुर्घटनाओं के मद्देनजर सुरक्षित यात्रा को लेकर लोगों के मन में हमेशा भय बना रहता है। सिग्नल का समय पर काम न करना, पटरियों की देखरेख और मरम्मत का अभाव और सबसे बड़ी गलती मानवीय चूक दुर्घटनाओं को न्योता देती है। पिछले दो-तीन महीनों में जितनी रेल दुर्घटनाएं हुईं हैं, वे बड़ी जनधन हानि की वजह भी बनी हैं। लगातार होती दुर्घटनाओं से लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा होती है। जब तक दुर्घटनाओं के वास्तविक कारणों की जांच नहीं होगी, स्थायी समाधान तलाशना भी आसान नहीं होगा।

अमृतलाल मारू, ईमेल से

▶ जाति पर विवाद क्यों

आज देश की राजनीति जाति और संप्रदाय के इर्द-गिर्द घूम रही है। यहां तक कि BJP, जो खुद को जातिवाद विरोधी पार्टी बताती है, वह भी इस समस्या से अछूती नहीं रही है। विपक्षी दलों ने जाति से जाति पूछने पर हंगामा खड़ा कर रखा है, जिससे जातिवाद की समस्या और बढ़ गई है। महर्षि दयानंद सरस्वती और डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे महान नेताओं ने जातिवाद समाप्त करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया, लेकिन हम उनसे कुछ नहीं सीखे। राहुल गांधी जाति आधारित जनगणना की बात कर रहे हैं, लेकिन जब सांसद अनुराग ठाकुर ने संसद में जाति पूछी तो हंगामा हो गया। संविधान और डॉ. आंबेडकर का नाम लेकर लोग सांप्रदायिकता और जातिवाद की राजनीति कर रहे हैं, जिससे देश का विकास बाधित हो रहा है। यह राजनीति न केव

वायनाड त्रासदी

पर्यावरणीय चेतावनी

वायनाड त्रासदी पर्यावरणीय चेतावनी अनदेखा करने के खतरनाक नतीजे प्रदर्शित करती है। लेकिन भारत में दुर्भाग्य से त्योहारों से लेकर त्रासदी तक हर चीज के 'राजनीतीकरण' की बुरी आदत विकसित हुई है और इसका प्रयोग विरोधियों के खिलाफ अवसर के रूप में किया जाता है। केरल के वायनाड में त्रासद भूस्खलन से 170 से अधिक लोगों की जानें गई हैं, लेकिन इसका भी राजनीतिक प्रयोग हो रहा है। इसने राज्य और केन्द्र सरकार के नेताओं के बीच गर्मागर्म बहस को जन्म दिया है। इस त्रासदी में जीवन और संपत्ति का भारी विनाश हुआ है और इसने आपदा के लिए तैयारी तथा पर्यावरणीय अनदेखी जैसे मुद्दों को सामने ला दिया है। भूस्खलन के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राज्य सरकार को जल्दी चेतावनी मिल गई थी, पर वह आवश्यक बचाव के उपाय करने में विफल रही। उन्होंने लापरवाही के लिए राज्य सरकार की आलोचना करते हुए संकेत किया कि यदि समय पर कार्रवाई की गई होती तो अनेक लोगों का जीवन बचाया जा सकता था। इस पर केरल के मुख्यमंत्री पिनारई विजयन ने फौरन शाह के दावों को खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने सभी उपलब्ध चेतावनियों पर कार्रवाई की और उसने संभावित प्राकृतिक आपदा का प्रभाव कम करने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाए थे। विजयन ने जोर दिया कि भूस्खलन की अभूतपूर्व विकरालता शीघ्र चेतावनियों के अनुमान से बहुत अधिक थी और राज्य के आपदा प्रबंधन बलों ने अथक रूप से स्थिति से निपटने के प्रयास किए। इस टकराव से कुछ हासिल नहीं हुआ। इससे न घायल लोगों को राहत मिली और न भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए किसी कार्ययोजना पर विचार हुआ। लेकिन इस प्रकार की बयानबाजी से केन्द्र और राज्य सरकारों ने स्वयं को 'क्लीन चिट' देने का प्रयास जरूर किया।

यह त्रासदी आपदा प्रबंधन की चुनौतियों को उजागर करते हुए राज्य और केन्द्र सरकारों के बीच समन्वित प्रयासों की आवश्यकता रेखांकित करती है। वायनाड त्रासदी ने पर्यावरण संरक्षण तथा प्रकृति की अनदेखी पर व्यापक विमर्श की आवश्यकता भी उजागर की है। केरल सरकार इस बात की दोषी है कि उसने 'पश्चिमी घाटों' पर बेलगाम विकास की अनुमति दी है, जबकि यह देश का एक सर्वाधिक संवेदनशील परिस्थितिकी तंत्र है। बार-बार आने वाली विभीषिकाओं के बावजूद केरल सरकार 'विकास' के नाम पर टिकाऊ गतिविधियां जारी रखे है। इसके कारण भूमि प्रयोग बदलने से घना वृक्षाच्छादन नष्ट हुआ है। इसने सदाबहार जलधाराओं व नदियों को मौसमी बना दिया है तथा मानसून के मौसम में बाढ़ आने का खतरा बढ़ा है। वायनाड भूस्खलन पर्यावरणीय संकेतों की अनदेखी करने के खतरनाक परिणामों की चेतावनी है। निर्वनीकरण व अनियोजित निर्माण ने वायनाड जैसे क्षेत्रों में प्राकृतिक विभीषिकाओं का खतरा पैदा कर दिया है। वायनाड भूस्खलन आपदा प्रबंधन में जवाबदेही तथा सक्रिय कदमों का महत्व भी उजागर करता है। ज्यादा महत्वपूर्ण रूप से यह हमारे पर्यावरण के सम्मान और देखभाल की आवश्यकता उजागर करता है। जंगल मिट्टी को स्थिर रखने तथा जल-चक्र को नियमित बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। निर्वनीकरण से परिस्थितिकी तंत्र बाधित होते हैं जिनसे भूस्खलन जैसी घटनाओं की आशंका बढ़ जाती है। वायनाड त्रासदी सरकारों, समुदायों और आम जनता का आह्वान करती है कि वे हम सबका अस्तित्व बनाए रखने के लिए पर्यावरण संरक्षण को प्राथमिकता प्रदान करें।

कौशल व रोजगार को प्राथमिकता

युवा सशक्तीकरण के लिए सरकार ने तीन परिवर्तनकारी योजनाओं की घोषणा की है। इनका उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में कौशल का विकास करना है।

दिनेश सूद
(लेखक, कौशल संवर्धन क्षेत्र से संबद्ध हैं)

केंद्रीय बजट की नौ सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रोजगार एवं कौशल विकास को बढ़ावा देना है। इस दृष्टिकोण से कौशल विकास के लिए तीन योजनाओं की घोषणा की गई है। पहली योजना में उच्च कौशल संवर्धन पाठ्यक्रमों के लिए अधिकतम कर्ज प्रदान करना है। इसके लिए संशोधित 'आदर्श कौशल कर्ज योजना' लाई गई है जिसमें प्रति वर्ष 1.5 प्रतिशत के ब्याज पर 1.5 लाख से लेकर 7.5 लाख रुपये तक कर्ज का प्रावधान किया गया है। इस योजना से युवाओं के सशक्तीकरण की उम्मीद है। इससे उनको उत्कृष्ट स्तर के कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच बढ़ाई जाएगी। इससे योग्य छात्रों के सामने आने वाली वित्तीय बाधायें काफी सीमा तक हटाने तथा उम्मीदवारों को भविष्योन्मुखी और उद्योगों में वांछित कौशल प्रदान करने में सहायता मिलेगी। इससे भविष्य के लिए तैयार और सशक्त कार्यबल तैयार होगा।

कौशल संवर्धन कर्ज बाजार में गैर-बैंकिंग वित्त कंपनियों-एनबीएफसी व माइक्रो-फाइनेंस संस्थानों की महत्वपूर्ण भूमिका को स्वीकार करते हुए कौशल विकास एवं रोजगार मंत्रालय-एमएसडीई ने योजना में महत्वपूर्ण परिवर्तन किए हैं। इस योजना में एनबीएफसी, माइक्रो फाइनेंस संस्थानों तथा छोटे फाइनेंस बैंकों को शामिल कर गारंटी के आधार पर कर्जों की व्यवस्था की गई है। इसके अंतर्गत कर्ज का 75 प्रतिशत हर साल 25,000 उम्मीदवारों को 7.5 लाख तक का कर्ज बिना किसी गारंटी के दिया जाएगा। इसका अर्थ है कि सरकार अपनी ओर से ऐसे कर्जों की गारंटी लेगी। सरकार ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि बिना जीवन्त कौशल कर्ज बाजार के अनेक नौजवान तथा इच्छुक उम्मीदवारों को आवश्यक वित्तीय समर्थन नहीं मिल पाता है जिसके कारण वे अपना कौशल संवर्धन तथा कौशल प्रशिक्षण नहीं प्राप्त कर पाते हैं।

कुशल क्षेत्र को कर्ज का निरंतर व सहज प्रवाह सुनिश्चित करने तथा कम आय वाले नौजवानों को विशेष कौशल पाठ्यक्रमों तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एमएसडीई ने पहले जुलाई, 2015 में क्रेडिट गारंटी फंड योजना शुरू की थी, लेकिन यह योजना अपनी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी।

पिछले दशक में इस योजना के अंतर्गत पैसे का ~~क्ष~~ प्रयोग कर्ज का 1.5 लाख रुपये तक सीमित आकार था, हालांकि मुद्रास्फीति के कारण पाठ्यक्रमों का खर्च और फीस बढ़ी थी। इसके कारण बहुत से अधिक खर्च वाले पाठ्यक्रमों को योजना से बाहर रखना पड़ा था। इसके साथ ही सरकार-प्रायोजित योजनाओं को वित्तपोषित करने के लिए निजी बैंकों में इच्छाशक्ति जगाना जरूरी था। 31 मार्च, 2024 तक पिछले दशक में इस योजना के अंतर्गत 10,077 कर्ज लेने वालों को केवल 115.75 करोड़ रुपये कर्ज ही दिया जा सका था। लेकिन नई माडल कौशल कर्ज योजना से सरकार की इस मुद्दे के प्रति अडिग प्रतिबद्धता प्रकट होती है जिसका उद्देश्य तेज गति से होने वाले तकनीकी परिवर्तनों को देखते हुए उच्च कौशल वाला कार्यबल तैयार करना है।

वर्तमान समय में मांग किए जाने वाले प्रासांगिक कौशलों को प्राप्त करने का खर्च काफी अधिक है। तथाकथित कुशल कार्यबल का केवल 5 प्रतिशत ही औपचारिक रूप से प्रशिक्षित है। इससे कौशल की कमी व्यापक रूप से सामने आती है जिसे तत्काल दूर किया जाना चाहिए। हालांकि, हर साल स्कूलों में 26.5 करोड़ बच्चे प्रवेश लेते हैं, पर उच्च शिक्षा तक पहुंचने पर उनकी संख्या घट कर केवल 4.3 करोड़ रह जाती है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-एनईपी 2020 के अनुसार स्कूली शिक्षा पास करने वाले अतिरिक्त पांच करोड़ बच्चों को उच्च शिक्षा के दायरे में लाया जाना चाहिए। इसके लिए न केवल प्रत्येक व्यक्ति की कौशल शिक्षा तक पहुंच होनी चाहिए, बल्कि ग्रामीण भारत के छात्रों की बड़ी संख्या को इसके दायरे में लाना होगा।

इस कमी को दूर करने के लिए आदर्श कौशल कर्ज योजना न केवल एक समाधान है, बल्कि यह आवश्यकता और तात्कालिक कदम है। कौशल अर्थव्यवस्था लगातार बाजार-संचालित होती जा रही है जिनमें नए युग के शिक्षण को कौशल विकास परिस्थितिकी से जोड़ा जाता है। शहरी और अर्ध-शहरी क्षेत्रों के नौजवान कौशल संवर्धन एवं आजीविका में सुधार के अवसरों की पहचान करते हैं। ऐसे में आदर्श कौशल कर्ज योजना जैसी पहल अपने दरवाजे अनेक कौशल पाठ्यक्रमों के लिए खोलती है जिसमें स्वास्थ्यरक्षा, सौंदर्य-बेहतरी, आईटी, एआई-डेटा साइंस, क्लाउड प्रयोग, डिजिटल मार्केटिंग, अतिथि सत्कार क्षेत्र, एनीमेशन, गेमिंग, ग्राफिक डिजाइनिंग तथा ड्रोन टेक्नोलोजी शामिल हैं। उद्योगों की बदलती गतिशीलता से संचालित ये पाठ्यक्रम बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर प्रदान करते हैं तथा वैश्विक स्तर पर नौकरियों की संभावनायें खोलते हैं। इससे नौजवानों को भविष्य के दरवाजे खोलने तथा अंतरराष्ट्रीय कॅरियर विकल्प खोजने में सहायता मिलती है।

दूसरी योजना का लक्ष्य अगले पांच साल में 20 लाख नौजवानों का कौशल संवर्धन करना है। कुल 60,000 करोड़ रुपये के आबंटन वाली इस योजना का लक्ष्य इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 1000 औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों-आईटीआई का 'हब एंड स्पोक' व्यवस्था के अंतर्गत उच्चीकरण करना है जिससे उन्मुखीकरण में सुधार होगा। यह एक महत्वाकांक्षी योजना है जिसका लक्ष्य नौजवानों को विशिष्ट-उद्योग कौशलों से समृद्ध कर उनको ज्यादा रोजगारों के उपयुक्त बनाना है। इसके लिए पाठ्यक्रम की विषयवस्तु व डिजाइन को उद्योगों की कौशल आवश्यकताओं के अनुरूप उच्चीकृत करना होगा। उदाहरण के लिए, उभरते आईटी क्षेत्र को साइबर सुरक्षा या डेटा विश्लेषण कौशलों की आवश्यकता है जिनको पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा। बजट में शामिल तीसरी योजना का उद्देश्य युवाओं को समग्र रूप से कौशल प्रदान करना है ताकि नौजवानों को सर्वोच्च 500 कंपनियों में इंटर्नशिप के अवसर मिल सकें। इस प्रकार की पहली योजना में अगले पांच साल में एक करोड़ नौजवानों को शामिल किया जाएगा। यह नौजवानों में बेरोजगारी समस्या का समाधान करने में गेमचेंजर हो सकती है। इस इंटर्नशिप योजना का खोजी दृष्टिकोण और संभावित प्रभाव इसे युवा जनसंख्या को भावी रोजगार दिलाने में प्रकाश की किरण जैसा है। इससे युवा बेरोजगारी दरों में काफी कमी आने की उम्मीद है। लेकिन इंटर्नशिप करना कठिन है क्योंकि इससे निराशा और हताशा का दुष्चक्र पैदा हो सकता है। एमबीए, इंजीनियरिंग, आदि पेशेवर डिग्री वाले छात्रों को स्नातक के बाद अच्छी नौकरियां व इंटर्नशिप प्राप्त करने में आसानी होगी। लेकिन यह परिदृश्य उन स्नातकों के लिए ज्यादा कठिन होगा और उनको नौकरियों के अयोग्य बनाएगा जो मानविकी विषयों से स्नातक होंगे और उनके पास बाजार के उपयुक्त तत्काल कोई कौशल उपलब्ध नहीं होगा।

प्रमुख कंपनियों में विभिन्न विषयों में शिक्षित युवा स्नातकों को इंटर्नशिप प्रदान करने वाली यह योजना एक 'गेम चेंजर' साबित हो सकती है। लेकिन इसके लिए योजना का समुचित व प्रभावी क्रियान्वयन बहुत जरूरी होगा। इसके लिए बड़ी कंपनियों को मजबूत इच्छाशक्ति दिखानी होगी और सरकार को इसके लिए उनको प्रेरित करना होगा। शायद भविष्य में सरकार इस योजना का दायरा बढ़ाने और कंपनियों के लिए इंटर्नशिप देना अनिवार्य करने पर विचार कर सकती है। कम से कम यह एक आकार से बड़ी कंपनियों के लिए अनिवार्य किया जा सकता है। सरकार इस उद्देश्य से कुछ विशिष्ट मानक भी निर्धारित कर सकती है।

कंपनियां अपने कार्पोरेट सोशल रिस्पांसिबिलिटी फंड-सीएसआर के अंतर्गत हर साल निश्चित संख्या में इंटर्न लेने की व्यवस्था कर सकती हैं। इस फंड से वे इंटर्नशिप के प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फंडिंग कर सकती हैं। ये फंड कंपनियों की पहल पर पर्यावरणीय व सामाजिक बेहतरी के लिए खर्च किए जाते हैं। सर्वाधिक महत्वपूर्ण रूप से इस योजना के अंतर्गत प्रदान की जाने वाली इंटर्नशिप से नौजवानों में नौकरियां प्राप्त करने की क्षमता बढ़ेगी। इस दौरान प्राप्त अपने सटीक अनुभव के आधार पर वे रोजगार प्राप्त करने में सफल होंगे। लेकिन रोजगार व नौकरी योग्य कौशल प्रदान करने में योजना का क्रियान्वयन, प्रभावशीलता व जवाबदेही सर्वाधिक महत्वपूर्ण होगी।

भारत का संतुलनकारी राजनय

> भारत सरकार पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक के बारे में अमेरिका और यूरोपीय चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है।

कुमारदीप बनर्जी
(लेखक नीति विश्लेषक हैं)

एक तरह से संतुलन बनाने की कोशिश में, भारत सरकार पिछले महीने राष्ट्रपति पुतिन के साथ पीएम मोदी की बैठक के बारे में अमेरिका और यूरोपीय चिंताओं को दूर करने की कोशिश कर रही है, जब कई नेता नाटो शिखर सम्मेलन के लिए वाशिंगटन में एकत्रित थे। राष्ट्रपति पुतिन ने मॉस्को में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए एक अतिरिक्त कदम उठाया, जो भारत के साथ दीर्घकालिक साझेदारी के बारे में अमेरिका को एक मजबूत संदेश देता है।

अमेरिका में वरिष्ठ अधिकारियों ने पीएम मोदी की मॉस्को यात्रा में शामिल दिखावे पर गहरी चिंता व्यक्त की, जबकि उन्होंने दोहराया कि कुछ भी महत्वपूर्ण हासिल नहीं हुआ। रूस के साथ द्विपक्षीय संबंध एक कठिन रस्सी है, जिस पर भारत पिछले दशकों में अमेरिका के साथ अपने बढ़ते जुड़ाव के बावजूद सावधानी से चलने में कामयाब रहा है। इसलिए, इस सप्ताह टोक्यो में क्वाड विदेश मंत्रियों का सम्मेलन, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अपने अमेरिकी समकक्ष एंथनी ब्लिंकन से मुलाकात की, महत्वपूर्ण था। संयुक्त बयान में स्पष्ट शब्दों में यूक्रेन में रूस की कार्रवाई की निंदा की गई, शायद पहली बार इस तरह के बहुपक्षीय आधिकारिक संचार में शामिल हुआ।

संयुक्त बयान में कहा गया, हम यूक्रेन में चल रहे युद्ध और उसके भयानक और दुखद मानवीय परिणामों पर अपनी गहरी चिंता व्यक्त करते हैं। हम अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप व्यापक, न्यायसंगत और स्थायी शांति की आवश्यकता को दोहराते हैं, जो संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के सम्मान सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर के उद्देश्यों और

सिद्धांतों के अनुरूप हो। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी द्विपक्षीय बैठकों और बाद में सार्वजनिक संदेशों में भी युद्ध के मैदान से दूर यूक्रेन संकट का स्थायी समाधान खोजने की आवश्यकता का उल्लेख किया था, साथ ही रूस द्वारा बच्चों के अस्पताल सहित लगभग 41 लोगों की हत्या करने वाले हमले की निंदा की थी। पीएम मोदी ने कहा, चाहे युद्ध हो, संघर्ष हो या आतंकवादी हमला हो, मानवता में विश्वास रखने वाला कोई भी व्यक्ति जान गंवाने पर दुखी होता है। लेकिन उसमें भी जब मासूम बच्चों की हत्या होती है, तो दिल दुखता है और वह दर्द बहुत भयानक होता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी की रूस यात्रा की निंदा की है। सरकारी अधिकारियों ने अब संकेत दिया है कि पीएम भू-राजनीतिक गतिशीलता को संतुलित करने और भारत और यूरोप के संबंधों को फिर से स्थापित करने के लिए अगस्त में यूक्रेन की यात्रा कर सकते हैं। इस बीच, क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में गाजा संकट और लाल सागर क्षेत्र में इसके फैलाव पर ध्यान केंद्रित करना जारी रहा, जिससे लोगों के जीवन पर असर पड़ रहा है और माल ढुलाई की लागत बढ़ रही है।

विदेश मंत्रियों ने संयुक्त रूप से संवाद किया, हम सभी पक्षों से अंतरराष्ट्रीय कानून, जिसमें अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून भी शामिल है, का पालन करने का आग्रह करते हैं। हम यूएनएससी संकल्प का स्वागत करते हैं और सभी संबंधित पक्षों से सभी बंधकों की रिहाई और तत्काल युद्धविराम की दिशा में तुरंत और लगातार काम करने का आग्रह करते हैं।

हम सभी पक्षों से सहायता कर्मियों सहित नागरिकों के जीवन की रक्षा करने और मानवीय राहत के तेजी से परिवहन की सुविधा के लिए हर संभव कदम उठाने का आह्वान करते हैं। हम इंडो-पैसिफिक सहित अन्य देशों को भी प्रोत्साहित करते हैं कि वे जमीन पर गंभीर मानवीय जरूरतों को पूरा करने के लिए अपने प्रयासों को बढ़ाएं। हम इस बात पर जोर देते हैं कि गाजा पट्टी के भविष्य की बहाली और पुनर्निर्माण को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा समर्थन दिया जाना चाहिए। हम दो-राज्य समाधान के हिस्से के रूप में इजरायल की वैध सुरक्षा चिंताओं को ध्यान में रखते हुए एक संप्रभु, व्यवहार्य और स्वतंत्र फिलिस्तीनी राज्य के लिए प्रतिबद्ध हैं जो इजरायल और फिलिस्तीनियों दोनों को न्यायपूर्ण, स्थायी और सुरक्षित शांति में रहने में सक्षम बनाता है।

भारत इस साल होने वाले क्वाड नेताओं के शिखर सम्मेलन की मेज़बानी करेगा, हालांकि, नवंबर में होने वाले महत्वपूर्ण अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इस समय के प्रमुख निर्धारक होंगे। राष्ट्रपति बिडेन जिन्होंने अतीत में ज्यादातर क्वाड कथा को आकार दिया है, वे चार के इस समूह पर एक स्थायी छाप छोड़ना चाहेंगे।

आप की बात

कोटे के भीतर कोटा

सुप्रीम कोर्ट ने एससी-एसटी आरक्षण में उपश्रेणियां बनाने, यानी कोटे के भीतर कोटा बनाने की अनुमति राज्यों को दे दी ताकि इन वर्गों में अधिक पिछड़ी जातियों को लाभ मिले। यह फैसला आरक्षण व्यवस्था पर दूरगामी प्रभाव डालेगा। सात न्यायाधीशों की संविधान पीठ में 6:1 के बहुमत से दिए गए फैसले से जस्टिस बेला एम. त्रिवेदी ने असहमति व्यक्त करते हुए राज्यों को यह अधिकार देना गलत माना। एससी-एसटी में भी ओबीसी की तरह क्रीमी लेयर लागू करने और आरक्षण को एक पीढ़ी तक सीमित करने जैसे अलग-अलग सुझाव दर्ज भी बहुमत से फैसला देने वाले न्यायाधीशों द्वारा दर्ज कराए गए। क्रीमी लेयर व आरक्षण एक पीढ़ी तक सीमित करने जैसे सुझावों को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। आरक्षण का यही सबसे स्याह पहलू है कि आजादी के बाद से ही आरक्षण का फायदा उठाने वाले अब भी आरक्षण को यथावत जारी रखना चाहते हैं। इसी वजह से आरक्षण का 75 प्रतिशत से अधिक फायदा आरक्षित वर्गों के ही गरीबों तक नहीं पहुंच पा रहा है। हालांकि, वोटबैंक राजनीति के चलते अब भी अधिक संख्या वाली दलित जातियों को पहले की तरह अधिक लाभ मिलने तथा कम संख्या वाली दलित जातियों को वंचित रहने की आशंका बनी हुई है।

सुभाष बुडावन वाला, रतलाम

कमला हैरिस को बढ़त

एक जनमत सर्वेक्षण के अनुसार, डेमोक्रेटिक अमेरिकी राष्ट्रपति उम्मीदवार कमला हैरिस ने सात स्विंग राज्यों में से छह में रिपब्लिकन डोनाल्ड ट्रम्प के खिलाफ बढ़त हासिल की है। कमला हैरिस का नाम सामने आने के बाद से ट्रम्प एक तरह से बचाव की मुद्रा में आ गए हैं। उन्होंने हैरिस पर व्यक्तिगत व नस्ली हमला करते हुए उनको बाइडेन से भी खराब उम्मीदवार तथा उनसे भी अधिक वामपंथी बता दिया है। उन्होंने कहा कि हैरिस पहले स्वयं को भारतीय मूल की महिला के रूप में पेश करती थीं, पर अब वे अश्वेत के रूप में सामने आ रही हैं। कमला हैरिस ने चेतावनी देते हुए कहा है कि ट्रंप को जो कुछ कहना हो, हमारे सामने कहें और राष्ट्रीय बहस में हिस्सा लें। मजेदार बात है कि जो ट्रंप पहले बाइडेन को बहस के लिए चुनौती देते थे, अब इससे कन्नी काट रहे हैं। उनको अहसास हो गया है कि भावी प्रथम अमेरिकी अश्वेत महिला के रूप में कमला हैरिस का पलड़ा उनसे लगातार भारी होता जा रहा है। रिपब्लिकन पार्टी की गर्भपात-विरोधी और आप्रवासी-विरोधी नीतियों के कारण अमेरिकी जनता का वही वर्ग और ज्यादा मजबूती के साथ कमला हैरिस के साथ आ रहा है जिसने जो बाइडेन को विजय दिलाई थी।

- जंग बहादुर सिंह, जमशेदपुर

आरक्षण की सीमा

सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस पंकज मिथल का विचार है कि आरक्षण केवल पहली पीढ़ी तक ही मिलना चाहिए। अगर कोई पहली पीढ़ी आरक्षण लेकर उच्च स्तर पर पहुँच गई है तो उसको इसका हकदार नहीं होना चाहिए। उन्होंने यह बात एससी-एसटी आरक्षण के कोटे में कोटा पर सुप्रीम कोर्ट में जजों के पेनल में हिस्सा लेने के दौरान कही। उनकी बात सही और तार्किक भी है। जिन्हें आरक्षण का लाभ मिल चुका है और वे व उनका परिवार उसे पाकर सक्षम हो चुका है और यह लाभ अब उनकी ही जाति के दूसरे वंचित लोगों को मिलना चाहिए। ऐसा न होने पर सक्षम लोग ही अपने लोगों को नुकसान पहुंचाते हैं। आरक्षण नीति में कुछ ऐसे परिवर्तन होने चाहिए जिसमें अधिक से अधिक लोगों को आरक्षण का लाभ देकर सक्षम बनाया जा सके। संविधान निर्माता डा. भीमराव आंबेडकर ने भी आरक्षण के जरिये अधिक से अधिक लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने की बात कही थी। उन्होंने कुछ मामलों में आरक्षण 10 वर्षों तक रखने का सुझाव दिया था। लेकिन अब आरक्षण वोटबैंक व चुनावी लाभ का हथकंडा बन गया है और भविष्य में इसकी सीमा और बढ़ने का खतरा मंडरा रहा है। यह स्थिति समाज कल्याण के बजाय निहित स्वार्थों को बढ़ावा देगी।

-शकुंतला महेश नेनावा, इंदौर

योगी का कठोर कदम

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कुछ अराजक युवाओं द्वारा स्कूटर सवार व्यक्ति व महिला पर गंदा पानी फेंकने और महिला के साथ छेड़खानी करने की घटना सामने आने के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कठोर कदम उठाया है। उन्होंने क्षेत्र के डीसीपी, एडिशनल डीसीपी और एसीपी का ट्रांसफर करने के साथ थाना इंचार्ज और पुलिस चौकी के सभी कर्मचारियों को निलंबित कर दिया है। कैमरों में दिखने वाले सभी अराजक व बेलगाम युवाओं को गिरफ्तार किया गया है। इसके लिए मुख्यमंत्री और यूपी पुलिस प्रशासन की सराहना की जानी चाहिए। यूपी पुलिस की कार्रवाई अपनी जिम्मेदारी न निभाने वाले पुलिस कर्मियों तथा अराजक शहरी युवाओं के लिए सबक है। योगी आदित्यनाथ का यह कठोर कदम उन विपक्षी राजनेताओं के लिए भी सबक है जो युवाओं को बहका कर प्रदेश की कानून व्यवस्था खराब कर मुख्यमंत्री और प्रदेश सरकार की छवि खराब करना चाहते हैं। विपक्षी दलों को ऐसी घटिया हरकतों से बचना चाहिए, नहीं तो 2027 में उनका फिर पूरी तरह सफाया हो जाएगा।

-वीरेंद्र कुमार जाटव, दिल्ली

पाठक अपनी प्रतिक्रिया ई-मेल से
responsemail.hindipioneer@gmail.com
पर भी भेज सकते हैं।